Follow us on :
bharatbhaskar.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

भारत भास्कर

हर खबर का असर

डाक पंजीयन - छ.ग. / रायपुर संभाग / 58 / 2021-2023

● वर्ष : 16 ● अंक-67 ● रायपुर, बुधवार 03 अप्रैल 2024 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य-2 रूपये ● रायपुर, नागपुर, भोपाल, लखनऊ एवं दिल्ली से प्रकाशित ● RNI-CHHHIN/2009/29179

सूर्योदय 6.22
सूर्यास्त 5.38
चैत्र कृष्ण पक्ष-नवमीं

सुविचार

शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है।
- स्वदेश तिवारी

3 टेकर पटवारी से पूरा ग्रामीण है हलाकान

5 आबकारी अधिकारी के संरक्षण में जिले भर में जमकर हो रही शराब की अवैध बिक्री

7 भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा दंतेवाड़ा जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न

संक्षिप्त समाचार

इस महीने पूरी तरह झुलसाएगी गर्मी, इतने दिन चलेगी लू

नई दिल्ली। बेशक अप्रैल के पहले दिन कुछ राज्यों में मौसम कूल है लेकिन मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अप्रैल से लेकर जून के बीच भीषण गर्मी पड़ेगी। इस समयावधि में तकरीबन 10 से 20 दिनों तक लू चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में तापमान को लेकर भी बदलाव दिख सकता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बताया कि इस साल देश में अप्रैल के अंत से प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां उत्पन्न होने का पूर्वानुमान है और संयोग से इसी दौरान लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में सभी हितधारकों के लिए पहले से तैयारी करना महत्वपूर्ण है। मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें आने वाले ढाई महीने प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ेगा।

कोर्ट ने शेख शाहजहां को 13 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेजा

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मामलों में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने आज यानी सोमवार को शेख शाहजहां को कोलकाता की सत्र अदालत में पेश किया था. इससे पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में जमीन हड़पने के मामलों में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख से बशीरहाट सुधार गृह में शनिवार को पूछताछ की. पूछताछ के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के बाद शेख की गिरफ्तारी दिखाई गई, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं. कोई आरोपी जब न्यायिक हिरासत में हो, उसे अन्यत्र दर्ज किसी अन्य मामले के संबंध में गिरफ्तार दिखाया जा सकता है.

चुनाव घोषणा पत्र को लेकर देशभर से मिले सुझाव: पीयूष गोयल

नईदिल्ली। भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र (चुनाव घोषणा पत्र) तैयार करने के लिए देशभर से सुझाव आए हैं। उन्होंने बताया कि आज समिति की पहली बैठक हुई, कुछ ही दिनों में अगली बैठक होगी और समाज, देश और जनता के हित को ध्यान में रखकर पार्टी अपने संकल्प पत्र को फाइनल रूप देगी। भाजपा मुख्यालय में सोमवार को हुई चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक के बारे में मीडिया को बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें 8 केंद्रीय मंत्री और 3 मुख्यमंत्री - गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित अन्य महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई और अलग-अलग विषय पर सभी ने अपने अमूल्य सुझाव दिए।

जयपुर ग्रामीण लोकसभा में बोले पीएम मोदी

राजस्थान वीरों और जुबान के पक्के लोगों की धरती-मोदी.....

जयपुर/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण लोकसभा में अपने वाली कोटपूतली विधानसभा से राजस्थान में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी। मोदी ने कहा कि 2019 में मैंने ढूंढाड़ से ही अपने चुनावी सभा की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने अपना संबोधन राम राम साञ्करके किया। इसके बाद उन्होंने मारवाड़ को भावनात्मक रूप से कनेक्ट करने के लिए स्थानीय लोकदेवताओं को नमन किया। मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान से जुड़ी ईआरसीपी, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, वन रैंक वन पेंशन, हर घर नल जैसी योजनाओं का जिक्र तो किया ही साथ ही आर्टिकल 370 और राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा कि मैं सामने जो दृश्य देख रहा हूंञ्राजस्थान की जनता जनार्दन का इतना बड़ा जन सैलाबञ्आपका ये उत्साह, जोश 4 जून का संकेत दे रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं। जयपुर का जलवा तो मैंने कुछ दिन पहले देखा, जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे। पूरी दुनिया ने जयपुर का मिजाज देखा है। साथियों 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा ढूंढाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है। मैं देख रहा हूं कि आप सबने भी निर्णय कर लिया है। देश की सियासत दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है। दूसरी तरफ देश को लूटने का मौके देखने वाली कांग्रेस पार्टी है। देश को परिवार मानने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। एक ओर दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है तो दूसरी और विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी, परिवार वादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा। राजस्थान ने 2014 में बीजपी को 25 की 25 सीटें और 2019 में एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थीं। अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। साथियों को 2024 का ये लोकसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। यह चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। यह चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। यह चुनाव भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। यह चुनाव आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए है। यह चुनाव किसानों की समृद्धि के संकल्प का चुनाव है। यह चुनाव घर-घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है। यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवार वादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। इसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं।

देश को बचाने के लिए ये चुनाव अहम- मोदी

जनता के दरबार में हार चुका इंडी एलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी झलक लगातार देखने को मिल रही है। यह पहला ऐसा चुनाव है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए यह चुनाव बहुत अहम है। आज देश में बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। मैं परिवार वादी पार्टियों और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि नहीं।

वह कुछ भी कहे मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार

वे मुझे गालियां देते हैं और यहां तक कह देते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। वह कुछ भी कहे मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं राजस्थान की धरती जो वीरों की धरती है और जुबान के पक्के लोगों की धरती है। मैं इस धरती पर कहना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। पिछली सरकारों ने जिसे पूछा तक नहीं मोदी ने उसे पूजा है। मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान निधी के करीब-करीब 20 हजार करोड़ रुपए भेजे हैं।

शाह बोले-दोनों में कोई मुकाबला नहीं

मोदी छुट्टी नहीं लेते और राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मनाते हैं..

बंगलूरू/ एजेंसी

देशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जीत हासिल करने के लिए तमाम दलों के बीच बयानबाजियों का सिलसिला भी जोर पकड़ रहा है। अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। दरअसल शाह उत्तरी बंगलूरू लोकसभा सीट में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को परिवारवादियों का गठबंधन करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कर्नाटक में भाजपा सभी 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के बीच कोई मुकाबला नहीं है। शाह ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी गर्मियां शुरू होते ही विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। दरअसल अमित शाह उत्तरी बेंगलूरू के पैलेस ग्राउंड में पांच लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान विपक्ष को परिवारवादियों का गठबंधन करार दिया। उन्होंने दावा किया कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 10 वर्षों के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया। उन्होंने कहा कि 2014 में कर्नाटक की जनता ने हमें 17 सीटों पर जीत दिलाई।

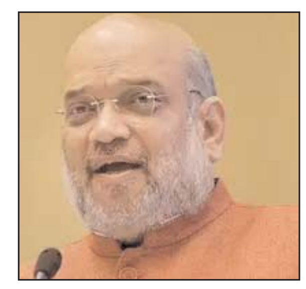

बड़े कारोबारी ने शूटर हायर कर कराई थी पत्नी की हत्या, 72 घंटे में वारदात का खुलासा

जमशेदपुर। जमशेदपुर की 39 वर्षीया ज्योति अग्रवाल की बीते शुक्रवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने उनके कारोबारी पति रवि अग्रवाल सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। रवि अग्रवाल ने इसके लिए 16 लाख रुपए की सुपारी पर शूटरों को हायर किया था। उन्हें तीन लाख रुपए बतौर एडवांस दिए गए थे और बाकी रकम हत्या के बाद दी जानी थी। सरायकेला जिले की पुलिस ने सोमवार को पूरे मामले का खुलासा किया। रवि ने साजिश का प्लॉट इस तरह रचा था।

खुद ही दिए रिटायरमेंट के संकेत

डीके शिवकुमार का रास्ता साफ करेंगे सिद्धारमैया...!

बेंगलुरु। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। कई दिनों तक खींचतान के बाद हाईकमान डीके शिवकुमार को राजी कर पाया था और फिर सिद्धारमैया को एक बार फिर मुख्यमंत्री का पद मिल गया। अब भी डीके शिवकुमार के समर्थक अकसर अपना दुख जाहिर करते रहते हैं। इस बीच सिद्धारमैया का एक बयान डीके शिवकुमार के समर्थकों को राहत दे सकता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी डीके शिवकुमार आज भी कर्नाटक की राजनीति में एक ध्रुव हैं। अब सिद्धारमैया ने रिटायरमेंट के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने मैसुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे।

चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐक्शन

राजीव कुमार ने जिलाधिकारियों और 12 एसपी का तबादला की

नई दिल्ली/ एजेंसी

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। 5 राज्यों असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही 12 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी तबादला हुआ है। आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान आयोग की ओर से की गई नियमित समीक्षा के तहत यह फैसला किया गया। स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपने जूनियर ऑफिसर को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा कि जिन अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें लोकसभा चुनावों के पूरा होने तक कोई चुनाव ड्यूटी नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग ने बिहार के भोजपुर और नवादा जिले के डीएम व एसपी का ट्रांसफर किया है। झारखंड के देवघर जिले के एसपी का तबादला हुआ है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, अनंतपुरामु और तिरुपति जिले के डीएम को बदले गए हैं। इसके अलावा प्रकाशम, पालनाडु, चित्तुर, अनंतपुरामु और नेल्लोर के एसपी का तबादला हुआ है। साथ ही गुंटूर के आईजीपी का भी तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को ओडिशा सरकार को 2 जिला धिकारियों, 5 पुलिस अधीक्षकों और एक पुलिस महानिरीक्षक समेत 8 अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया।

सड़क हादसे में चालक समेत दो बच्चों की मौत

मेरठ। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में चालक समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। अमरोहा के कोचिंग संस्थान से दो गाड़ियों में सवार होकर बच्चे दिल्ली के जामिया मिलिया छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे थे। इस कोचिंग संस्थान में ही बच्चे रहते भी हैं। एक गाड़ी 24 वर्षीय अनस निवासी अमरोहा चला रहा था, जिसमें 11 बच्चे सवार थे।

लोकसभा चुनाव में किससे होगी टक्कर?

नंतनाग-राजौरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे गुलाम आजाद

अनंतनाग/ एजेंसी

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अनंतनाग-राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगे। उनकी पार्टी डीपीएपी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी और पार्टी के साथ अपने पांच दशक लंबे सफर को खत्म कर दिया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद आजाद ने अपना खुद का राजनीतिक संगठन-डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) बनाया। डीपीएपी नेता ताज मोहिउद्दीन ने यहां संवाददाताओं से कहा, आज डीपीएपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और हमने फैसला किया है कि (पार्टी अध्यक्ष) गुलाम नबी आजाद अनंतनाग-राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2014 में उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता जितेंद्र सिंह से हारने के बाद आजाद के लिए यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने मंगलवार को कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनावों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ चर्चा को तैयार हैं। हालांकि, अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली जेकेएपी ने वैचारिक मतभेदों के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है। अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर मोहिउद्दीन ने कहा कि उस मोर्चे पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

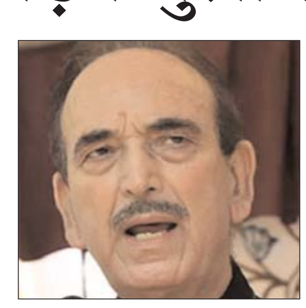

संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली

सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप नेता और सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत दे दी। गौरतलब है कि मामले में पिछले छह माह से जेल में संजय सिंह बंद हैं। जिसके बाद से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने संजय सिंह की जमानत पर कहा कि सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं सकते हैं। सत्यमेव जयते... मैं अदालत के इस फैसले का स्वागत करता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, मैं अदालत के इस फैसले का स्वागत करता हूं... सीपीआई के महासचिव डी राजा ने आप नेता और सांसद संजय सिंह की जमानत पर कहा कि यह केंद्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति को करारा झटका है। इससे दूसरों में भी उम्मीद जगेगी, जमातन भी मिलेगी। मुझे विश्वास है कि वे मामले में रिहा भी होंगे। सत्य की जीत होगी और न्याय की जीत होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है। ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है, यही हमारे लोकतंत्र और स्वतंत्र अदालत की खासियत है। आप नेता और सांसद संजय सिंह को मिली जमानत पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह एक अच्छी खबर है। ईडी ने भी इसका विरोध नहीं किया। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत सशक्त और मजबूत रुख है। शिवसेना(यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करती हूं। इससे पता चलता है कि भाजपा विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संजय सिंह चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की बातों को समाने रखेंगे। आप सांसद संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर ईडी के पास कोई मजबूत सबूत होता तो वह जमानत का विरोध करती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि उनके पास कोई मजबूत सबूत नहीं था। बिना किसी कारण के सलाखों के पीछे संजय सिंह को रखा गया था। एनसीपी(शरद चंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ अन्याय हुआ था। अब उन्हें मामले में जमानत मिली है, जो अपने आप में एक अच्छी खबर है। देश के सामने जल्द ही सच्चाई सामने आएगी।

हम लोग जश्न नहीं मनाएंगे, देश की जनता सब देख रही-अनीता सिंह

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आखिरकार दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत मिल गई। वह करीब पिछले छह महीनों से जेल में बंद थे। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि हम सभी अभी खुशी नहीं मनाएंगे। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है।अनीता सिंह से जब संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद पूछा गया कि कितनी खुशी है तो उन्होंने कहा कि अभी खुशी हमारी अधूरी है। अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि हमारे तीन बड़े भाई, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं।

फैशनेबल ड्रेसेज और एसेसरीज से भरा रहे आपका वॉर्डरोब

हर किसी की चाहत होती है कि उसका वॉर्डरोब फैशनेबल ड्रेसेज और एसेसरीज से भरा रहे। अपने वॉर्डरोब को फूल करने के चक्कर में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि फैशन का ट्रेंड बदलता रहता है। ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि एक टाइमलेस वॉर्डरोब के बारे में सोचा जाए।

फैशन ट्रेंड की भविष्यवाणी थोड़ा मुश्किल काम है। आज जो ट्रेंड है, वह कल होगा या नहीं, इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह भी पूरी तरह से सच नहीं है कि आप लिटेस्ट फैशन को जज न कर सकें। वैसे भी कुछ बेसिक आइटम्स की जरूरत हमेशा बनी रहती है। इन्हें अपने वॉर्डरोब में शामिल करके अपने वॉर्डरोब को फैशनेबल बना सकती हैं। आप अपने वॉर्डरोब में कुछ टाइमलेस ड्रेसेज, ज्वैलरी और फुटवियर्स शामिल करें, ये आपके काम आएंगे।

वाइट शर्ट

फैशन डिजाइनर सौमित्र कुमार की मानें, तो वॉर्डरोब के लिए वाइट टेलर्ड शर्ट सबसे जरूरी है। दरअसल, वाइट शर्ट या टॉप के साथ कुछ भी मैच करके पहना जा सकता है। वाइट शर्ट के साथ कोई भी एसेसरीज आसानी से मैच हो जाती हैं। आप चाहें तो वाइट शर्ट में डिफरेंट कट्स, स्टाइलिश स्लीव्स या फंकी कॉलर्स डिजाइन करवा सकती हैं। वहीं, फैब्रिक में सिल्क, शिफॉन व जॉर्जेट टेक्सचर ट्राई करें। इन फैब्रिक्स में फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और इन्हें हर सीजन में पहना जा सकता है।

शिफ्ट ड्रेसेज

अक्सर लड़कियां किसी ओकेजन को ध्यान में रखकर ड्रेसेज परचेज करती हैं। यही वजह है कि अगर उन्होंने फॉरमल ओकेजन के लिए ड्रेस ली है, तो वह उसे नाइट पार्टी में पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में शिफ्ट ड्रेसेज बेस्ट ऑप्शन हैं। इन्हें आप डे व नाइट दोनों मौकों पर पहन सकती हैं। दरअसल, एक सिंपल ड्रेस से भी मैजिक क्रिएट किया जा सकता है। जरूरी यह है कि उसे स्मार्टनेस के साथ कैरी किया जाए। शिफ्ट ड्रेसेज पहनने से फेमिनिन लुक तो आता ही है तथा इन्हें कैरी करके आप और भी ज्यादा स्टाइलिश लग सकती हैं।

जैकेट

यदि आप एक ही ड्रेस पहनकर बोर हो गई हैं तो जैकेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। इन दिनों मिलिट्री जैकेट ट्रेंड में है। इन्हें आप सॉलिड कलर्स में ले सकती हैं। इससे आपको क्लासिक लुक मिलेगा। यदि आप नाइट आउट पर जा रही हैं तो शाइनी जैकेट बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप लेगिंग्स के साथ मैच करके पहन सकती हैं। इससे आपको पूरा पार्टी लुक मिलेगा और आप काफी ग्लैमरस लगेंगी।

ब्लैक ड्रेसेज

कोई भी वॉर्डरोब ब्लैक ड्रेसेज के बिना कम्प्लीट नहीं होता है। इसे किसी भी ओकेजन पर पहना जा सकता है। चाहे आप स्लिम दिखना चाहती हों या अपने लुक में क्विक चेंज चाहती हों, ब्लैक ड्रेस के साथ हल्की-फुल्की ज्वैलरी कैरी करें। इसका मिक्स एंड मैच स्टाइल से खुद को डिफरेंट लुक दिया जा सकता है। ब्लैक ड्रेस के साथ सिल्वर जूलरी बहुत फबती है। आप इनके साथ अपने वॉर्डरोब में ट्रेंडी शूज भी शामिल कर सकती हैं। इनके कलर सीजन के मुताबिक चुनें। इन्हें आप सिल्वर, गोल्ड और प्लेन ब्लैक में चुन सकती हैं। यह आपकी पर्सनैलिटी पर खूब फबेगा।

जींस

हर किसी के पास एक पेयर जींस होना लाजिमी है, लेकिन उसका फिट होना भी बहुत जरूरी है। फैशन डिजाइनर सौम्या अरोड़ा कहती हैं, जींस हर ऐज में और हर ओकेजन में पहन सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि जींस ब्रांडेड ही हो। आप जींस के साथ खूब एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। अगर आप कैजुअल आउटिंग पर जा रही हैं, तो इसके साथ बैगी टी-शर्ट व स्नीकर्स पहन सकती हैं। यदि आप को पार्टी में जाना है तो जींस के साथ स्टाइलिश टॉप और हाई हील्स ट्राई कर सकती हैं। यह ध्यान रखें कि जींस की क्वॉलिटी अच्छा हो।

पर्ल

जिस तरह डायमंड हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट हैं। वैसे ही पर्ल भी कभी फैशन से आउटडेटेड नहीं होते हैं। आप एसेसरीज में पर्ल नेकलेस या बैंगल्स जरूर रखें। इन्हें आप हर तरह के आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकती हैं। अगर आप रियल पर्ल नेकलेस पसंद नहीं करती हैं तो फेक नेकलेस खरीद सकती हैं।

बच्चे को सारी सुविधाएं देने के साथ-साथ उन पर निगरानी

प्रतिस्पर्धा और दिखावे के मौजूदा दौर में अभिभावकों की इच्छा होती है कि उनका बच्चा किसी भी मामले में कम न रहे। इसके चलते वे अपनी संतानों को सहूलियत, पढ़ाई और 'ज़माने के साथ चलने' के नाम पर विभिन्न चीज़ें प्रदान करते हैं, कई बार तो सामर्थ्य से भी बढ़कर। वैसे तो कोई भी वस्तु या सुविधा अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन दो सिद्धांत यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह लाभदायक होगी या हानिकारक। बच्चों पर मोबाइल फोन, गाड़ी, इंटरनेट कनेक्शन, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड आदि सुविधाओं के असर का आकलन इन पैमानों पर किया जा सकता है कि उसे फ़ायदे की जगह नुक़सान तो नहीं हो जाएगा और माता-पिता के लिए अप्रिय स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी।

कई बार काम में व्यस्त माता-पिता छोटे बच्चों को बहलाए रखने या मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन थमा देते हैं। इस उम्र में मोबाइल का चमकता स्क्रीन बच्चे की आंखों पर स्थायी रूप से बुरा असर छोड़ सकता है। इसके अलावा, उसके सामाजिक समायोजन और भाषा के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन की हलचल और किरदारों की नाटकीयता के चलते भावनाओं का प्रदर्शन और एकाग्रता भी प्रभावित होती है। इस दौरान भले ही बच्चा शांत बैठा रहे, पर यह उसके शारीरिक विकास को अवरुद्ध करता है। हर बार मोबाइल थमा दिए जाने से उसमें ज़िद करने और अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

6-12 वर्ष

इस उम्र के पढ़ाई के नाम पर मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा दी जाने लगी है। वैसे तो कोरोना के ऑनलाइन दौर में यह मजबूरी थी, परंतु अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। विशेषज्ञ कहते हैं कि बढ़ते बच्चों को इंटरनेट पर फटाफट सर्च करके पके-पकाए नतीजे हासिल करने के बजाय मेहनत करके किताबों में खोजने की आदत डालनी चाहिए। इससे उनकी बुनियाद मज़बूत होगी। यही वजह है कि तमाम कैलकुलेटर उपलब्ध होने के बावजूद बच्चों से गणित का अभ्यास कराया जाता है और तथ्य याद कराए जाते हैं। इस उम्र में इंटरनेट की अधिक मदद लेने से परिश्रम करने, दिमाग़ लगाने, चीज़ों को समझने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, आंखों को नुक़सान पहुंचता है सो अलग। दूसरी तरफ़, मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और विभिन्न तरह के वीडियो देखने की लत भी लग सकती है। समझ के अभाव में कई बार बच्चे ऑनलाइन ग़लत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और साइबर बुलिंग या धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम की अधिकता उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इससे बच्चों में नींद और एकाग्रता की कमी भी देखी जाती है।

13-18 वर्ष

किशोरवय के इस दौर में अभिभावकों को बच्चे की ज़रूरत के साथ-साथ उसके शौक़, फ़ैशन और पीयर प्रेशर का ध्यान भी रखना होता है। इस उम्र में मोबाइल फोन और इंटरनेट के अलावा दुपहिया वाहन, स्मार्टवॉच जैसी चीज़ें भी दिलाई जाने लगी हैं। इस समय इंटरनेट की सीमित ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बड़ों की निगरानी में और सिर्फ़ पढ़ाई के उद्देश्य से। ऐसा न हो तो इंटरनेट के असीमित उपयोग से बच्चा वास्तविक और काल्पनिक दुनिया में अंतर नहीं रख पाएगा और संभव है कि वास्तविक दुनिया से उसका संपर्क कट जाए। अभिभावकों की निगरानी न होने पर ऑनलाइन गेम, अनजान लोगों से दोस्ती, पोर्न की लत जैसे बड़े ख़तरे भी हो सकते हैं। जहां तक स्मार्टवॉच जैसी सुविधा का सवाल है, तो वह

स्कूल में भी ध्यान भटकाएगी और स्मार्टफोन से लगातार जोड़े रखेगी, जिसका कोई लाभ नहीं है। उन्हें वाहन देना भी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में रोमांच की चाह तो होती है, पर निर्णय क्षमता गतिविधियों के नतीजों की समझ पूर्ण विकसित नहीं होती। एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि वयस्कों की तुलना में किशोरवय वाहन चालकों से दुर्घटना की आशंका चार गुना अधिक होती है।

18 वर्ष से अधिक

इस उम्र में बच्चे पढ़ाई के लिए कई बार अपने घर से दूर भी जाकर रहते हैं, इसलिए मोबाइल फोन, इंटरनेट, गाड़ी के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा भी ज़रूरी लगने लगती है। हालांकि इनसे पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन उपयोग को सीमित अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे, क्रेडिट की एक लिमिट होनी चाहिए और उसे अभिभावक के फोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, ताकि हर ख़र्च की जानकारी उन तक पहुंचे। वाहन भी दिखावे के बजाय आवागमन में सुविधा के लिए ख़रीदा जाना चाहिए।

बदलाव ऐसे लाएं

अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं तो अभिभावक उनसे वह सब वापस ले लेते हैं। इससे बच्चे विद्रोही भी हो जाते हैं। ऐसे मामलों में माता-पिता इन बातों का ध्यान रखें-

- माता-पिता पहले बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें समझाएं कि इस सुविधा को कम करने या वापस लिए जाने की आवश्यकता क्यों है।
- नियम बनाएं कि छोटे बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल अभिभावक की निगरानी में ही करेंगे और जिस काम से मोबाइल लिया गया है, उसी तक सीमित रहेंगे।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक और हिंसक कार्यक्रमों के लिए हतोत्साहित करें। ओटीटी प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वीडियो आधारित सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्टेड मॉड का उपयोग करके अनुचित वेबसाइट/की-वर्ड्स को अवरुद्ध किया जा सकता है।
- कोई भी चीज़ या सुविधा कभी भी सज़ा के तौर पर वापस ना लें।
- बच्चों से यह स्पष्ट कर दें कि प्राइवेसी के नाम पर असीमित छूट नहीं दी जाएगी। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर माता-पिता फ्रेंडलिस्ट में रहेंगे और आवश्यक होने पर फ्रेंड्स के बारे में जानकारी भी लेंगे।
- सही तरीक़े से सुविधाओं का उपयोग करने पर माता-पिता बच्चों की प्रशंसा भी करें।
- हर सुविधा के उपयोग के लिए एक उपयुक्त समय सीमा निर्धारित करें। बच्चों के साथ-साथ माता-पिता भी अपने लिए सभी सुविधाओं के उपयोग का समय निश्चित रखें।
- बच्चों को सही और ग़लत में अंतर करना सिखाएं तथा उन्हें समय-समय पर नैतिक मूल्यों से अवगत कराएं।

प्रकृति और महिलाएं एक-दूजे की पर्याय

लगातार बढ़ता तापमान, सूखते जलस्रोत और प्रदूषित होता वायुमंडल यह सब संकेत हैं कि आने वाला समय और भी कठिन संकट ला सकता है।

लगातार बढ़ता तापमान, सूखते जलस्रोत और प्रदूषित होता वायुमंडल यह सब संकेत हैं कि आने वाला समय और भी कठिन संकट ला सकता है। तो क्यों ना संभलते हुए इन सब समस्याओं से निकलने के प्रयास किए जाएं क्योंकि छोटे-छोटे प्रयास ही सार्थक होकर किसी बड़े कार्य को पूर्ण करेंगे। शायद पर्यावरण बचाव के यज्ञ में हर एक का योगदान एक-एक आहुति से कम न हो।

एक वृक्ष पहल

हमारे देश में प्रकृति व पृथ्वी को मां का ही दर्जा दिया है। सिर्फ इसलिए कि वे अपने पुत्रों व परिवार के संरक्षण के लिए समर्पित हैं इसलिए क्यों न हम अपने परिवार में एक ऐसी संस्कृति को पनपाएं जो प्रकृति के संवर्धन में भी जुटे और अपने पारिवारिक उत्सव को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ सके। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में परिवारजनों का जन्मदिन हो सकता है परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण कर पृथ्वी के उस कर्ज की मुक्ति का रास्ता भी खोला जा सकता है। जिसमें हमने जो कुछ प्रकृति से लिया है या लेंगे उसकी वापसी का रास्ता भी बन सके। इससे प्रकृति प्रेम भी पनपेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार भी तैयार होंगे। इसी तरह परिवार के अन्य कार्यों जैसे शादी, ब्याह, मुंडन इन सभी को पर्यावरण के किसी कार्य से जोड़ लेना चाहिए। ऐसा ही करके शायद हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं का हिस्सा बना पाएंगे।

बिन पानी सब सून

बूंद-बूंद पानी की तरस को इस वर्ष तकरीबन 11 राज्यों के 33 करोड़ लोगों ने देखा है। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक के गांवों में रहे, जहां गांव के गांव पलायन करने को मजबूर हो गए। यहां तक की गले तर करने तक के लिए रेल के जरिए पानी को भेजा गया। यदि इसी तरह के हालात रहे तो यह सभी के लिए दुखदायी होंगे। इसलिए हम सभी को यह सोचना होगा कि जब पानी के बिना सब सूना है तो क्यों न बूंद-बूंद से ही घट भरा जाए। जब तक हम सचेत नहीं होंगे तब तक और किसी को नहीं सिखाया जा सकता है। तो क्यों न इस पानी बचाव की शुरुआत घर से ही प्रारंभ की जाए। घर के हर सदस्य को पानी की बचत के साथ पानी को सुरक्षित रखने के उपाय अपनाने होंगे तभी तो हम इसका संरक्षण कर पाएंगे।

महिलाओं का योगदान

इतिहास को खंगाले तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा में हमेशा से महिलाओं को ही अग्रणीय पाया गया है। विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी गांव की सरल महिला थीं, जिसकी वन वृक्ष की लड़ाई विश्व प्रसिद्ध हुई।

आखिर पूरे हिमालय में वनों के प्रति यह संवेदनशीलता उस महिला को ही क्यों भायी? वनों के पतन की पीड़ा ने उन्हें ही क्यों झकझोरा था? बात गौरा देवी की ही नहीं बल्कि राजस्थान के विश्नोई समुदाय की भी है, जहां महिलाओं ने पेड़ों पर चिपककर उनके काटने का विरोध किया था। आखिर नोबेल पुरस्कार विजेता अफ्रीका की मथाई को ही करोड़ों वृक्षों को लगाने की सुध क्यों आई। ऐसे ही अपने देश व विदेशों की बहुत-सी कहानियां हैं, जिनमें महिलाएं वृक्षों के प्रति गंभीर संवेदनशीलता दर्ज कर चुकी हैं। इतिहास गवाह है कि वन लगाने की बात हो या फिर इसको बचाने की मुहिम हो उस पर महिलाएं ही अग्रणी रही हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा में सबसे पहले महिलाओं को ही याद किया जाता है ताकि उनके और प्रयास से हम आने वाले समय में भी कुछ बेहतर प्रयास कर सकें। असल में इसका कारण वृक्ष और महिलाओं की समान प्रवृत्तियां है। दोनों ही समाज के लिए समर्पित हैं। दोनों के ही समान व्यवहार हैं। महिला और वृक्ष समाज के सृजन व बेहतरी के लिए बिना किसी शर्त के सदियों से सेवा में जुटे हैं। निस्वार्थता दोनों का मूल चरित्र है। इसलिए यह कहना कदापि अतिश्योक्ति नहीं होगी कि दोनों के बिना प्रकृति पृथ्वी और समाज अर्थविहिन व पंगु कहलाएगा। सच यह है कि मूल भाव से दोनों ही एक-दूसरे को समझते ही नहीं है बल्कि पूरक भी हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों महिलाएं वनों व वृक्षों से ज्यादा बेहतर तालमेल रखतीं। यह स्वतः ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रकृति व प्रवृत्ति की समान झलक दिखाई देती है।

आपके पूरे घर को रीप्रेज़ेंट करता है लिविंग रूम

घर का लिविंग रूम वह कमरा होता है जो आपके पूरे घर को रीप्रेज़ेंट करता है। इसे सजाने के लिए आप अपनी पसंद की चीजें लगाते हैं, उसे अलग-अलग कलर स्कीम और पैटर्न्स से सजाते हैं।

जब आपके किसी के घर मेहमान बन कर जाते हैं तो उनका लिविंग रूम देखकर ही आप पूरे घर का अंदाजा लगा लेते हैं। वैसे ही जब कोई आपके घर आता है तो भी यही बात मायने रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि घर का लिविंग रूम वह कमरा होता है जो आपके पूरे घर को रीप्रेज़ेंट करता है। इसे सजाने के लिए आप अपनी पसंद की चीजें लगाते हैं, उसे अलग-अलग कलर स्कीम और पैटर्न्स से सजाते हैं। आपकी सजावट पर हमें कोई शक नहीं है बस हम आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि कर रहे हैं कि कैसे आप अपने लिविंग रूम को और बेहतर बना सकतीं हैं।

- कंट्रॉस- लिविंग रूम में दीवारों पर कंट्रॉस कलर ट्राई करें या दो रंगों से दीवारों को रंगें। यह रूम को थोड़ा हटके लुक देगा। रंगों में लाइट-डार्क, ब्लैक-व्हाइट, रेड-व्हाइट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इन्हीं में से किसी कलर कॉम्बिनेशन को चुन कर आप पूरे कमरे के लुक को डिसाइड कर सकतीं हैं।
- फूलदान - लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखें। इसके लिए नकली फूलों के साथ विशेष अवसर पर प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल करें। यह लिविंग रूम को सजाने का सबसे आसान और सीमित बजट में निपटने वाला तरीका है।
- फोटो फ्रेम्स- अपने लिविंग रूम को क्लासी और इमोशनल टच देने के लिए दीवार पर अपनी फैमेली की फोटो लगा सकते हैं। चाहे तो पूर्वजों की तस्वीरों को भी लिविंग रूम में जगह दे सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपके लिविंग रूम में शांति और सौम्यता का वातावरण आ जाएगा।
- पर्दे- लिविंग रूम में पर्दे लगाएं लेकिन ध्यान रखें कि वे कमरे में आनेवाले प्राकृतिक उजाले को ना रोकें। आजकल पारदर्शी पर्दे चलन में हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकतीं हैं या फिर अगर कुछ अलग करना चाहतीं हैं तो क्रोशिए से बने पर्दे लगाएं। ये मनचाहे रंग में मिल जाएंगे और कमरे में अंधेरा भी नहीं करेंगे और आपका कमरा शानदार दिखेगा।
- सेटअप- अपने फर्नीचर और एसेसरीज का सेटअप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करें। कमर खचाखच भरा हुआ ना लगे इसका खास ध्यान रखें। अच्छी लाइटिंग स्कीम चुनें। इस बात का ध्यान रखें कि कमरा व्यवस्थित लगे। साफ-सुथरा हो।

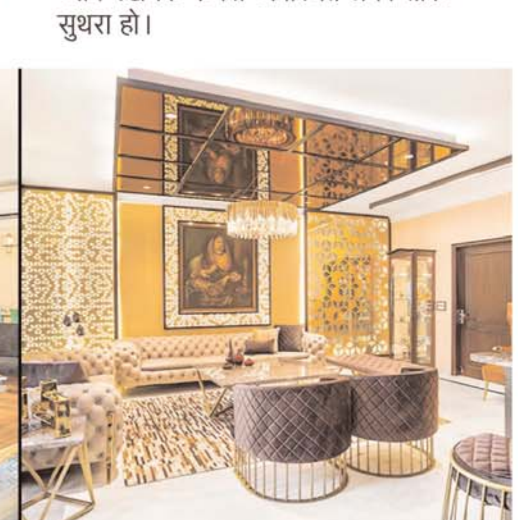

टेकर पटवारी से पूरा ग्रामीण है हलाकान

जाँच दल के सामने ही पटवारी और कोटवार को ग्रामीणो ने घेरा, कोटवार के जरिए पटवारी वसूलता है पैसा

ग्रामीणों ने पटवारी व कोटवार को हटाने और दंडात्मक कार्रवाई की मांग

बिलासपुर:- सरकारी सिस्टम मे वसूली बाज कर्मचारी से आम जनता रहते हैं परेशान हर परिस्थितियो मे पैसा वसूलने मे लगे रहते है। ताजा मामला बेलतरा तहसील के ग्राम टेकर का मामला है जहां ग्रामीणो ने पटवारी की अवैध वसूली के खिलाफमोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है की टेकर गांव का पटवारी कोटवार के माध्यम से गांव के किसानो की फौती, नामांतरण, आय, जाति वगैरह राजस्व कामों के लिए अवैध वसूली करता है और पैसे की मांग करता है। पटवारी के द्वारा ग्रामीणों से आए दिन दुर्वयवहार भी किया जाता है। पूरे मामले की जाँच के लिए बेलतरा तहसीलदार ने जाँच कमेटी बनाकर टेकर गांव भेजा जहां जाँच समिति के सामने ही ग्रामीणों ने पटवारी के करतूतो की पोल खोल कर रख दी जिससे पटवारी की बोलती बंद हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणो ने पटवारी को हटाने की मांग किया। शिकायत कर्ताओ मे प्रमुख रूप से प्रदीप वर्मा, हौंस राम, पतिराम, पुष्कर, विनोदकुमार, हरीश नामदेव, बलराम आदि ग्रामीण जन रहे। पूरे मामले का विस्तार इस प्रकार से है ग्राम टेकर में ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर के समक्ष शिकायत होने तथा कार्यालय के अधीन विभागीय राजस्व बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा गठित टीम द्वारा आज उपस्थित हुए। जांच के दौरान लगभग 100 ग्रामीण उपस्थित रहे पूछ ताछ के दौरान ग्रामीण द्वारा बताया की हल्का पटवारी हर कार्य हेतु पैसों की मांग किया जाता है। नामांतरण, फौती, खाता बटवारा यहां तक की आय, जाति, निवास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु ग्रामीणों से पैसे की मांग की जाती है। पटवारी का ग्रामीणों से व्यवहार अच्छा नहीं रहता। पटवारी कोटवार के माध्यम से पैसा लिया करता है। पूरे ग्रामीणो में रोष व्याप्त है पटवारी को गांव से हटाना चाहते हैं। उचित दणनात्मक कार्यवाही चाहते हैं।

मौके में दुर्गा प्रसाद धीवर उपस्थित हुए और उनके द्वारा बताया गया उनकी बटवारा हेतु 45000/- रुपए लिया गया है जबकि आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ।परंतु नाम में भी त्रुटि हुआ हैं। मौके पर अन्य लोगों द्वारा भी शिकायतें की गई है जिसमें मनहरण पिता मोदी राम ने बताया कि पिछले दो वर्षों से मेरे बच्चे के जाति प्रमाण पत्र के प्रतिवेदन हेत हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। उल्टा पटवारी द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में नहीं है। वंशावली होने के बाद प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। मौके में उपस्थित लक्ष्मी प्रसाद धीवर द्वारा बताया की भू-स्वामी घासीराम धीवर के फौती नाम करने हेतु पटवारी के पास गया परन्तु पटवारी द्वारा मुझे छह हजार रुपए कि मांग किया पैसे नहीं दिया तो मेरे फौती नामांतरण अभी तक नहीं हुआ है। मौके में उपस्थित राम अवतार धीवर द्वारा बताया गया आवेदक के माता समुन बाई का फौती उठाना है परन्तु पटवारी छह हजार रुपए की मांग किया कोटवार घर-घर जाकर पैसा मांगने जाता है। पटवारी खुद पैसा नहीं लेता मौके में जोहन लाल उपस्थित होकर बताया कि पटवारी द्वारा नामांतरण हेतु 12000हजार मांग किया गया पैसा नहीं दिया तो नामांतरण लम्बित है। पटवारी बिना पैसे के मांग के बिना काम नहीं करता जाती आमदानी हेतु 5000 हजार लिया गया है मौके में चंद्रभूषण वर्मा उपस्थित होकर बताया कि मेरे से पटवारी प्रमाण पत्र हेतु 5000 हजार लिया पटवारी खुद पैसा लिया है। कृषक दिनेश कुमार धीवर फौति एवं बटवारा के नाम पर 45000 हजार रुपए लिया गया उसके बाद भी काम अधुरा पड़ा हुआ है। कृषक सुरेश कुमार वर्मा मौके पर जांच देखने जाने पर छह हजार की मांग पटवारी कर रहे हैं। वही पटवारी पर्ची बनाने के लिए ?8000 लिया गया है।बताया गया कि छोटे-छोटे कामों के लिए पटवारी द्वारा बहुत मनमानी करते हुए लूटपाट कर रहे हैं। पटवारी को हटाने के साथ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण द्वारा पटवारी को ग्राम से हटाकर सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता- प्रदीप वर्मा, हाउस राम, पतिराम, पुष्कर कश्यप, विनोदकुमार, हरीश, नामदेव वर्मा, बलराम, राजेशकुमार, नितेश, लाला, राम अवतार, आकाश, सूर्यप्रकश, चंद्रिका, सुदामा बाई, चन्द्रिका कश्यप,लव कश्यप,कौशल साहू, मनहरण लाल, जगन्नाथ, कमलेश्वर विश्वकर्मा, रोहित साहू, विनोद वर्मा,दिलहरण आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।

ग्रामीणो के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत की गई थी जिसका जांच किया गया है। लोगों का कथन लिया उच्च अधिकारियों को भेजा गया।

प्रकाश चन्द साहू
तहसीलदार बेलतरा

कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने किया मतदान दल को दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण

जांजगीर-चांपा 02 अप्रैल 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारागांव में मतदान अधिकारियों को दिए जा रहें प्रशिक्षण का निरीक्षण किया।

इस दौरान कलेक्टर कहा कि निर्वाचन में सकुशल मतदान संपन्न कराने में मतदान अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन से जुड़ी हर प्रक्रिया और प्रपत्र के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों का दायित्व है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करें, जिससे निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया संपादित की जा सके। कलेक्टर ने संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की जानकारी मतदान अधिकारी को दी। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल कुमार रावटे, अपर कलेक्टर श्रीमती लवीना पांडेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती आराध्या राहुल कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जांजगीर क्रमांक 01, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलौदा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अकलतरा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पामगढ़ एवं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारागांव में दिए जा रहे मतदान दल प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

स्वीप कार्यक्रम : स्कूली छात्रों ने दिया लोकसभा चुनाव में मतदान का संदेश

मतदान के प्रति जागरूकता के लिए आगे आए हाई स्कूल के छात्र

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- 2 अप्रैल 2024 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। लोकसभा निर्वाचन में लोगों की शत प्रतिशत सहभागिता के उद्देश्य को पूरा करने जिले के स्कूली छात्र भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जिले के सभी ब्लॉक के हायर सेकण्डरी स्कूलों के छात्रों ने जागरूकता कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोगो को मतदान का संदेश दिया।

जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय में स्थित हायर सेकण्डरी स्कूल के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और शत-प्रतिशत मतदान का संदेश दिया गया। बैनर और जागरूकता से संबंधित पोस्टर के साथ छात्रों ने मतदान में भागीदारी का संदेश दिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाखासार, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजी, शासकीय स्कूल लोखंडी, बहतराई और जूनापारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तखतपुर के छात्रों ने रंगोली, मेंहदी, ड्रॉईंग प्रतियोगिता और जागरूकता संबंधी नारो से अपने क्षेत्र में मतदान के लिए लोगो को प्रेरित किया। हाथों में मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर के जरिए छात्रों ने लोगो को मतदान में सहभागिता का संदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें महिला समूह, हाई स्कूल के छात्र, विभिन्न सामाजिक संगठन और विभागीय स्तर पर मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम किये जा रहे है, और लोगो तक 7 मई को मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है।

स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारत में विकास के नए युग का सूत्रपात करने के लिए डिजिटाइजेशन की रणनीति को बढ़ावा दिया

नई दिल्ली। स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी ऑल-न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी की घोषणा के साथ पहले ही नए युग का सूत्रपात कर दिया था। नए युग की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए कंपनी ने यूजर के जुड़ाव, उपभोक्ताओं को कंपनी की योजनाओं में शामिल करने और डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए कई डिजिटल गतिविधियों की शुरुआत की है। इससे बिक्री में काफी उछाल आया है और कंपनी अपने ग्राहकों या प्रशंसकों के ज्यादा नजदीक पहुंची। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रैंड डायरेक्टर पेट्र जेनेबा ने कहा, लगातार बदलते डिजिटल फ्लक, प्लेटफॉर्म और मीडियम को देखते हुए उपभोक्ताओं के अनुभव और उनके सफर को यादगार बनाने के लिए नए तरीकों को अमल में लाना बहुत जरूरी हो गया है। हमारी डिजिटल रणनीति यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि हमारे प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज उपभोक्ताओं और फैंस तक उनके पसंदीदा रूप में पहुंचे। अभी तक कंपनी को नेम योर स्कोडा कैंपेन के तहत अपनी जल्द ही लॉन्च होने वाली ऑल-न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए 1,50,000 एंट्रीज या नामों के सुझाव मिले हैं। हाल ही मे कंपनी का 24 घंटे का डिजिटल कैंपेन समाप्त हुआ, जिसमें कंपनी ने भारत में अपने कार्यकाल के 24 वर्ष पूरा करने का जश्न मनाते हुए एक दिन या 24 घंटे में 709 स्कोडा कारों की बुकिंग की। हमने स्कोडा गियर हेड्स कम्युनिटी के माध्यम से स्कोडावर्स इंडिया एनएफ्टी को और विस्तार दिया है। इसके साथ हम बड़े और विविधता से भरपूर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए निरंतर नई पहल कर रहे हैं और नई रणनीति को अपना रहे हैं।''

लगभग साढ़े 5 हजार कर्मचारी कराएंगे लोकसभा चुनाव

चुनाव आयोग के साफ्टवेयर में रैण्डमाईजेशन से कर्मचारियों का हुआ चयन

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- 02 अप्रैल 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान कराने वाले कर्मचारियों का आज चयन किया गया। निर्वाचन आयोग के साफ्टवेयर में रेण्डमाईजेशन के जरिए चुनाव कराने वाले कर्मचारी चयनित किये गये। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में प्रक्रिया पूर्ण की गई। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर जिले में 1524 मतदान केन्द्र शामिल हैं। इन केन्द्रों में ड्यूटी के साथ ही 20 प्रतिशत रिजर्व कर्मचारी सहित लगभग साढ़े 5 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। मतदान दल का गठन अभी नहीं हुआ है। अगले चरण में रैण्डमाईजेशन के जरिए ही मतदान दल का गठन किया जायेगा। आदर्श मतदान केन्द्रों के लिए मेन्यूअल तरीके से ड्यूटी लगाई जायेगी। जिले की छहों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर 96 आदर्श मतदान शामिल हैं। जिनमें संगवारी मतदान केन्द्र, युवा मतदान केन्द्र एवं दिव्यांग मतदान केन्द्र आते हैं। एनआईसी के तकनीकी निदेशक अरविन्द यादव द्वारा निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में प्रथम चरण के रैण्डमाईजेशन की गई। इसके तहत पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एक एवं दो का चयन किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान एवं संयुक्त कलेक्टर प्रवेश पैकरा भी उपस्थित थे।

अनिवार्य सेवा से जुड़े लोग अब डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान

इच्छुक मतदाता को 12 से 17 अप्रैल तक देना होगा आवेदन

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- 2 अप्रैल 2024 को लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित करते हुए इनके कर्मचारियों को पहली बार डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अनिवार्य सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, विद्युत, ऐसे मीडिया कर्मी जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी होगा, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी-कर्मचारी डाक मतपत्र का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता कर्मचारी-अधिकारी को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में लोकसभा सामान्य निवार्चन 3 चरणों में होना है। जिले में लोकसभा निर्वाचन तीसरे चरण में होगी, जिसके लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल तक है। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नं., वोटर आईडी नं. एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाईन एप्प का उपयोग किया जाए, जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। प्रारूप 12घ के भाग 1 के साथ-साथ जिला स्तर पर नियुक्त विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा इस आवेदन को भाग 2 में सत्यापित किया जाए। आवेदन के साथ कर्मचारी का वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न किया जाए। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये तीन दिन लगातार प्रात: 09 से 05 बजे तक संचालित किया जाएगा। वे सभी कर्मचारी जो प्रारूप 12 घ में आवेदन करेंगे एवं पात्र पाये जायेंगे वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से पोस्टल वोटिंग सेंटर में ही मतदान कर सकेंगे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर वोटिंग की पात्रता नही होगी। अत: जो भी व्यक्ति प्रारूप 12घ में आवेदन करें, उन्हें जिले में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर पर ही मतदान की व्यवस्था से अवगत कराया जाए। पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान हेतु नहीं जा सकने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस को अपना मत दर्ज करने की पात्रता नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट डालने हेतु सक्षम होंगे उनसे प्रारूप 12घ नहीं भरवाये जाए। जिला स्तर पर उपरोक्त अधिसूचित अनिवार्य सेवाओं के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी एवं यथा-शीघ्र पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त कर इसे जिले में डाक मतपत्र हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों (सूची संलग्न) को प्रदान करना होगा।

सार-समाचार

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक ली

जिले में आगामी लोकसभा निर्वाचन एवं त्यौहारो को ध्यान में रखते हुए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जांजगीर-चांपा 2 अप्रैल 2024 / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा एवं पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में आगामी लोकसभा निर्वाचन एवं त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जिले के परंपरा अनुरूप शांति एवं सौहार्द पूर्ण तरीके से भक्त माता कर्मा जयंती, ईद-उल-फित्तर, डॉ अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती एवं रामनवमी मनाने के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान कहा गया कि लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही धारा 144 लागू है। सभी प्रकार के आयोजनों तथा रैली, जुलुस, डीजे के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति अनिवार्य रूप से लिया जाए। लोकसभा निर्वाचन के दौरान एफ़एसटी टीम से चेक पॉइंट पर नियमित रूप से निरीक्षण करने और बाहर से आने वाले वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल कुमार रावटे, अपर कलेक्टर श्रीमती लवीना पांडेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए संयुक्त कलेक्टर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर अधिकृत

बिलासपुर :- 2 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रैली, सभा, रोड शो, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति के लिए जिले के सभी सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुमति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर अनुमति जारी करेंगे। इसके साथ ही प्रचार वाहनों, विमान और हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति जारी करने हुए संयुक्त कलेक्टर श्री साहू को अधिकृत किया गया है।

रेत का अवैध परिवहन करते 4 हाईवा पकड़ाए

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- 02 अप्रैल 2024 को अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इस सिलसिले में मस्तुरी ब्लॉक के पचपेड़ी में बिना रायल्टी पटाये रेत परिवहन करते हुए 4 हाईवा वाहन पकड़े गए। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर पुलिस एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। वाहनों को जब्त कर पचपेड़ी थाना परिसर में खड़ी की गई है। खनिज अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एशिया सोसाइटी इंडिया सेंटर बोर्ड ने संगीता जिंदल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया

मुंबई- एशिया सोसाइटी इंडिया सेंटर बोर्ड ने संगीता जिंदल को अपने निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की घोषणा की है। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हो गई है। एशिया सोसाइटी इंडिया सेंटर की सीईओ इनाक्षी सोबती ने कहा, ''मुझे एशिया सोसाइटी इंडिया सेंटर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संगीता जिंदल का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने दक्षिण एशिया में हमारे मिशन को बहुत समर्थन दिया है और भारत और दक्षिण एशिया में समकालीन कला को सपोर्ट करने का उनका काम एक परिवर्तनकारी शक्ति रहा है। मैं दक्षिण एशिया में एशिया सोसाइटी के काम को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।'' संगीता जिंदल आर्ट इंडिया की प्रेसिडेंट और जेएसडब्ल्यू फ़ाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। यह फ़ाउंडेशन जेएसडब्ल्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज की सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार है। पिछले बीस वर्षों में वह जेएसडब्ल्यू फ़ाउंडेशन का नेतृत्व कर रही हैं, इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सृजन, स्थानीय खेल विकास और कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाया है। उन्होंने 1992 में जिंदल आर्ट्स सेंटर की स्थापना की और 1994 में भारत की प्रमुख कला पत्रिका 'आर्ट इंडिया' की स्थापना की। वह काला घोड़ा कला महोत्सव की संकल्पना करने वाली टीम में शामिल थीं और उन्हें 2004 में आइजनहावर फैलोशिप से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हम्पी फ़ाउंडेशन की स्थापना की है जिसने हम्पी में तीन मंदिरों में संरक्षण कार्य का जिम्मा उठाया। वह एशिया सोसाइटी की ग्लोबल ट्रस्टी और राष्ट्रीय संस्कृति कोष के निदेशक मंडल की सदस्य हैं। साथ ही, विश्व स्मारक कोष की ट्रस्टी, टेडएक्स गेटवे की एडवाइजर और आईएमसी लेडीज विंग कला, संस्कृति और फिल्म समिति की सदस्य भी हैं। 1956 में जॉन डी. रॉकफेलर तृतीय द्वारा स्थापित, एशिया सोसाइटी एक गैर-पक्षपाती, गैर-लाभकारी संस्था है जिसके प्रमुख केंद्र और सार्वजनिक भवन न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और हांगकांग में हैं, और कार्यालय लॉस एंजिल्स, मनीला, मेलबर्न, मुंबई, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, सियोल, सिडनी, टोक्यो, वाशिंगटन डी.सी. और ज्यूरिख में हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर राजनैतिक हंगामा

कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

भारत की संसद ने 1947 में हुए भारत विभाजन के कष्टकारी नतीजों को ध्यान में रखते हुए 2019 में अपने नागरिकता अधिनियम को संशोधित करते हुए उसमें प्रावधान किया था कि भारत के उस हिस्से से जिसे । इंग्लैंड ने 1947 में अपनी संसद में एक अधिनियम पारित करके मजहब के आधार पर भारत के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान के नाम से अलग देश घोषित कर दिया था । लेकिन इंग्लैंड की संसद द्वारा यह अधिनियम पारित करने से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में भारत को विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया । उसी प्रस्ताव के आधार पर इंग्लैंड की संसद ने पाकिस्तान बनाने का अधिनियम पारित किया था । जाहिर था कांग्रेस के प्रस्ताव और इंग्लैंड की संसद के अधिनियम का संयुक्त परिणाम यह हुआ कि करोड़ों भारतीय नागरिकों की भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो गई और वे रातों रात पाकिस्तान के नागरिक घोषित कर दिए गए । उनमें बहुत से नागरिक तो ऐसे थे जो नए देश पाकिस्तान के नागरिक बन कर ख़ुश थे । लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी थे जो उनकी भारतीय नागरिकता को उनकी इच्छा के बिना छीन लिए जाने से दुखी थे । इसी तरह शेष बचे भारत में भी बहुत से भारतीय नागरिक ऐसे थे जो अपनी भारतीय नागरिकता छोड़कर नए देश पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहते थे । लेकिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन को लेकर तो प्रस्ताव पारित कर दिया लेकिन उस प्रस्ताव में नागरिकता को लेकर पैदा होने वाले इस संकट पर या तो ध्यान नहीं दिया या फ़िर वह ज़मीनी हालात से इतना कट चुकी थी कि उसे इसका अन्दाज़ा ही नहीं हुआ । यहाँ तक इंग्लैंड का प्रश्न था उसे इस स्थिति पर विचार करने की जरुरत ही नहीं थी । लेकिन डा0 भीमराव रामजी आम्बेडकर , जो बाद में भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने , नागरिकता को लेकर उत्पन्न इस गम्भीर संकट को पहचान गए थे । उन्होंने कहा था कि देश के बहुत से मुसलमान अपने लिए पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश की माँग कर रहे थे । इसका अर्थ था कि वे भारतीय नागरिकता त्यागना चाहते थे । अब जब पाकिस्तान बन गया है तो ऐसे मुसलमानों को पाकिस्तान में ही चले जाना चाहिए । इसी प्रकार देश के जिस हिस्से को पाकिस्तान बनाया जा रहा था , उस हिस्से में रह रहे लाखों हिन्दु-सिख पाकिस्तान बनाने का विरोध कर रहे थे और वे भारतीय नागरिकता ही रखना चाहते थे । आम्बेडकर का प्रस्ताव था कि पाकिस्तान बनने पर इस प्रकार की आबादी की अगला बदली की व्यवस्था भी करनी चाहिए । राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भी मोटे तौर पर यही मत था । सरदार पटेल ने तो असम में जाकर अपने सार्वजनिक भाषण में भी यह बात कही थी कि अब पाकिस्तान बन गया है इसलिए जो मुसलमान भारतीय नागरिकता रहने से दुखी हैं वे पाकिस्तान जा सकते हैं । लेकिन नेहरु ने तुरन्त इसका विरोध किया । उधर पाकिस्तान में जो हिन्दु-सिख भारत की नागरिकता रखना चाहते थे , पाकिस्तान की नई सरकार उनको बलपूर्वक भारत नहीं आने दे रही थी । आम्बेडकर ने इस पर नेहरु को एक पत्र भी लिखा कि वे पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डालें कि वह ऐसे हिन्दु-सिखों को भारत में आने से न रोकें । लेकिन भारत सरकार की इस क्रूर नीति के बावजूद लाखों हिन्दु-सिख अपनी भारतीय नागरिकता बचाने के लिए पाकिस्तान से चल पड़े । लाखों इस चाहत में ही मारे गए और लाखों सब कुछ लुटाकर ही भारत पहुँचने में कामयाब हो सके । लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान के दूर दराज़ के इलाक़ों में रहते थे वे भारत नहीं आ सके । कांग्रेस के नेता उन दिनों पाकिस्तान में रह रहे हिन्दु-सिख-बौद्धों से अपील कर रहे थे कि वे वहीं बने रहें । कुछ हिन्दु-सिख-बौद्धों ने कांग्रेस नेताओं की उस अपील को यथार्थ मान कर उस पर विश्वास कर लिया और पाकिस्तान में बने रहे । पाकिस्तान का निर्माण करवाने में इंग्लैंड की सहायता करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पहले ही भाषण में कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दु-सिख-बौद्ध को डरने की जरुरत नहीं है । उनको अपने मजहब को मानने की पूरी आजादी होगी । कुछ हिन्दु-सिख-बौद्ध जिन्ना के इस धोखे में भी आ गए ।

लेकिन इस सभी से यह तो स्पष्ट हो गया था कि भारत सरकार को अपने नागरिकता अधिनियम को विभाजन के उपरान्त उत्पन्न हालात के अनुसार संशोधित करना जरुरी था क्योंकि इस कृत्रिम विभाजन के परिणाम दशकों तक ही नहीं बल्कि शताब्दियों तक आते रहेंगे । परिणाम तो विभाजन के तुरन्त बाद ही आने शुरु हो गए । पूर्वी बंगाल (पहले पूर्वी पाकिस्तान और अब बंगला देश) से जल्दी ही हिन्दु-सिख-बौद्ध वहाँ से भाग कर भारत आने लगे । वहाँ उनका रहना मुश्किल हो गया । इस्लाम में मतान्तरित होने के लिए वे तैयार नहीं थे । पाकिस्तान के विधि मंत्री जोगेन्द्र नाथ मंडल को भी पाकिस्तान से भाग कर भारत आना पड़ा । हालत यहाँ तक गड़बड़ा गए कि पश्चिमी पाकिस्तान से हिन्दु-सिख भाग कर अफ़ग़ानिस्तान में चले गए । लेकिन इस प्रकार के हालत में भारत सरकार को अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करना चाहिए था ताकि जो लोग अपने पर बलपूर्वक थोपी गई पाकिस्तान नागरिकता को लेने को तैयार नहीं थे बल्कि अपनी भारतीय नागरिकता को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे । लेकिन भारत सरकार अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का पालन करने से बचती रही और लाखों हिन्दु-सिख-बौद्ध कष्टकारी जीवन व्यतीत करने के लिए अभिषप्त होते रहे ।

बंगला देश बनने के बाद इसके विपरीत एक अजीब दौर प्रारम्भ हो गया । बंगला देश से लाखों की संख्या में मुसलमान अवैध तरीक़े से भारत में घुसने लगे । ये वे लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश काल में मुसलिम लीग व ब्रिटिश सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे 'भारत तोड़ो अभियान' में भाग लिया था जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हो गया और इन्हें इनकी माँगी हुई पाकिस्तानी नागरिकता मिल गई । इनके भारत में आने का कारण क्या है ? क्या वहाँ का सरकार (पाकिस्तानी या बांग्लादेशी) इन्हें इस्लाम मजहब के कारण तंग कर रही है ? ऐसा तो सम्भव ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और बंगला देश दोनों ही सांविधानिक लिहाज़ से भी इस्लामी देश है । तब येभारत में क्यों आ रहे हैं ? क्या भारत में काम काज की तलाश में आते हैं ? यदि ऐसा है दो इन्हें बाक़ायदा विधि के अनुसार भारत का वीज़ा व वर्क परमिट लेकर आना चाहिंए । लेकिन ये बिना वीज़ा के आते हैं । यदि इनको आज पचहत्तर साल बाद लगता है कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान की नागरिकता की जरुरत नहीं थी । वह एक ऐतिहासिक ग़लती थी तो इन्हें पाकिस्तान और बंगला देश में उसी प्रकार अभियान चलाना चाहिये जैसा इन्होंने 1947 से पहले भारत को तोड़ कर के 'पाकिस्तानी नागरिकता' के लीए किया था । लेकिन अब अभियान की दिशा यह होगी कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी नागरिकता समाप्त कर च यानि भारत का विभाजन समाप्त कर , इन्हें भी भारत की पुरानी नागरिकता मिल जानी चाहिए । लेकिन ऐसा कोई आन्दोलन पाकिस्तान या बंगला देश में फ़िलहाल चलता दिखाई नहीं दे रहा ।

पाकिस्तान और बंगला देश से हिन्दु-सिख-बौद्ध को भारतीय नागरिकता देने को 'सामान्य शरणार्थी' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए । वे यदि भारत की नागरिकता की माँग कर रहे हैं तो शरणार्थी के नाते नहीं बल्कि यह उनका अधिकार है क्योंकि उनकी भारतीय नागरिकता बिना उनकी इच्छा के छीनी गई थी । यह अलग बात है कि आधुनिक शब्दावली में उनके लिए शरणार्थी शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है । दरअसल भारत सरकार ने विभाजन से उत्पन्न इस दशकों से लम्बित समस्या का समाधान निकालने के लिए ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया है । इस संशोधन के अनुसार कोई भी हिन्दु-सिख-बौद्ध-जैन-ईसाई जिसे मजहब के आधार पर पाकिस्तान, बंगला देश और अफ़ग़ानिस्तान में उत्पीड़ित किया गया हो और वह 2014 से पहले भारत आ गया तो उसे आवेदन करने पर भारतीय नागरिकता मिल जाएगी । यह एक प्रकार से विभाजन का प्रायश्चित है । वैसे भी यह अधिनियम पाकिस्तान, बंगला देश और अफ़ग़ानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को शरण देने या नागरिकता देने का प्रावधान नहीं करता । इसका सम्बंध केवल उन हिन्दु सिखों बौद्धों से है जो 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं । अर्थात कम से कम इन्हें छह साल तो भारत में रहते हुए हो ही गए हैं । इस संशोधन में क्क्क से छह साल पहले भारत में आ चुके अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता वापिस करने का वैधानिक रास्ता निकाला गया है । यह संशोधन क्क्कमें रह रहे अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होता । यह संशोधन क्क्कसे अल्पसंख्यकों को भारत में भाग आने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं करता क्योंकि यह संशोधन केवल उन अल्पसंख्यकों पर लागू होता है जिन्हें भारत मे रहते हुए छह साल हो गए हैं । दरअसल यह अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मूल प्रावधानों को नहीं बदलता बल्कि यह उन अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की वैकल्पिक व तीव्रगामी व्यवस्था स्थापित करता है जो कम से कम छह साल से भारत मे रह रहे हैं । इसे फ़ास्ट ट्रैक व्यवस्था भी कहा जा सकता है ।

वैसे किसी उचित केस में शरण देने या न देने की परम्परा हमारे देश में रही है । नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से इन सामान्य विधि विधानों में कोई रुकावट नहीं पड़ती है । इटली की नागरिक रही सोनिया गान्धी ने इन्हीं विधि विधानों के सहारे भारत की नागरिकता हासिल की थी । पूर्व सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव की बेटी स्वेतलाना ने भी एक भारतीय से शादी की थी और भारत में शरण माँगी थी लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इन्दिरा गान्धी ने उसे शरण देने से इन्कार कर दिया था ।

अमेरिका का दोहरा चरित्र/औरों को नसीहत ख़ुद मियाँ फज़ीहत : अमेरिका का मीडिया और कुछ सीमा तक अमेरिका की विधायिका इस बात को लेकर बहुत चिन्ता ज़ाहिर कर रही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने से भारत का पंथ निरपेक्ष चरित्र ख़तरे में पड़ गया है । भारत में किसी को शरण देने के लिए सरकार मज़हब को आधार कैसे बना सकती है ? इसको लेकर अमेरिका हलकान हो रहा है । वह कुछ सीमा तक चिन्ता और कुछ सीमा तक घुड़की का प्रयोग कर रहा है । भारत पंथ निरपेक्ष बना रहे , इसका दायित्व अमेरिका ने अपने उपर ले लिया लगता है । नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में उन हिन्दु, सिख , ईसाई , बौद्ध और जैन पंथ के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है जो पाकिस्तान , बंगला देश और अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 तक येन केन प्रकारेण भारत में आ गए थे । अमेरिका का विधायिका में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि इस सूची में मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि सभी से समानता का व्यवहार किया जाएगा । इसलिए मुसलमानों को इस सूची में शामिल न किए जाने से भारत का संविधान ख़तरे में पड़ गया है और पंथ निरपेक्ष चरित्र पर दाग लग गया है । अमेरिका को इस बात की चिन्ता सबसे ज्यादा रहती है कि किसी भी देश में मज़हब के आधार पर मतभेद नहीं होना चाहिए । इसलिए उसने अपने यहाँ 1968 में international religious freedom act नाम से एक क़ानून बनाया जिसमें विदेशों में अमेरिकी दूतावासों को यह अधिकार दिया कि वे प्रत्येक देश की राजनीति पर नज़र रखें । यद्यपि यह अमेरिका की अनाधिकार चेष्टा ही कही जाएगी । इन्तहा तो यह है कि अमेरिका ने इस अधिनियम के अन्तर्गत International Religious Freedom के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय राजदूत भी नियुक्त कर रखा है ।

लेकिन अमेरिका के क़ानूनों में नागरिकता और शरणार्थी को लेकर वैधानिक स्थिति क्या है, इसको भी परखना जरुरी है । अमेरिका के सभी अधिनियम या क़ानून यूएस कोड में संग्रहीत हैं । इस कोड में अधिनियमों का वर्गीकरण करने के बाद प्रत्येक वर्ग को क्रमांक दिया जाता है । इस प्रकार राष्ट्रीयता, अप्रवासी , नागरिकता और शरणार्थी सम्बंधी क़ानून क्रमांक 8 के अन्तर्गत संग्रहीत हैं । अमेरिका का The Immigration and Nationality Act 1965 इसी के अन्तर्गत आता है । 21 नवम्बर 1989 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया । इस संशोधन का प्रस्ताव न्यू जर्सी के एक सीनेटर लौटनवर्ग ने रखा था , इसलिए यह संशोधन लौटनवर्ग संशोधन के नाम से जाना जाता है । यह 101वीं कांग्रेस में पारित होने के कारण यह पब्लिक ला 101-167 कहलाता है । इस संशोधन में प्रावधान किया गया है कि पूर्व सोवियत यूनियन , एस्टोनिया और लिथुवानिया के यहूदी , एवेंजिलिकल क्रिश्चियन , यूक्रेन कैथोलिक मज़हब को मानने वाले नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण दी जाएगी । यह प्रावधान शुरु में केवल एक साल के लिए था लेकिन इसकी उम्र बढ़ा कर इसे अभी तक प्रभावी बनाया हुआ है । 2004 में इस का विस्तार करते हुए प्रावधान किया गया कि ईरान से आने वाले यहूदी, क्रिश्चियन और बहाई मज़हब को मानने वाले ईरानियों को भी अमेरिका में शरण दी जाएगी । इतना ही नहीं मज़हबी आधार पर शरण पाने वाले इन वर्गों को अमेरिका की सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है ।

अमेरिका की विधानपालिका ,अमेरिका में शरण माँगने वालों का मज़हब के आधार पर भेदभाव क्यों करती है ? वहाँ का संविधान तो इस प्रकार के साम्प्रदायिक या मज़हबी भेदभाव की अनुमति नहीं देता । 1868 में अमेरिकी संविधान में चौदहवाँ संशोधन हुआ था जिससे संविधान में Equal Protection Clause जोड़ी गई थी लेकिन इसके वाबजूद शरण दिए जाने वाले वर्गों में ईरान के मुसलमानों और पूर्व सोवियत यूनियन के मुसलमान नागरिकों को इस सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया ? ये अनेक प्रश्न हैं जो अमेरिका की सरकार से पूछे जा सकते हैं । अमेरिका की मज़हबी आधार पर भेदभाव करने वाली यह नीति उसकी विदेश नीति का हिस्सा है । ईरान की न तो सीमा अमेरिका ले लगती है और न ही दोनों देशों का इतिहास साँझा है । यही स्थिति सोवियत यूनियन की है । इसलिए शरणार्थी से मज़हबी आधार पर भेदभाव अमेरिकी की बड़ी राजनीति का हिस्सा है । भारत और पाकिस्तान का तो इतिहास भी साँझा है और 1947 में उसका विभाजन ही मज़हबी आधार पर हुआ था । लेकिन ताज्जुब है जिनसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए वे भारत से प्रश्न पूछ रहें हैं कि आपने शरण दिए जाने वाले वर्गों की सूची में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया ? यह प्रश्न तो संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछा जाना चाहिए कि आप पूर्व सोवियत यूनियन के नागरिकों को शरण व नागरिकता देने के लिए मज़हब के आधार पर मतभेद क्यों कर रहे हो ? अमेरिका शरणार्थी जैसे शुद्ध मानवीय प्रश्न को भी अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा है । लेकिन यह उसका अपना आन्तरिक मामला है इसलिए किसी को दख़लन्दाज़ी करने का अधिकार नहीं है । लेकिन अमेरिका इसी प्रश्न पर भारत को प्रश्नित कर रहा है । इसका न तो उसे नैतिक अधिकार है और न ही सांविधानिक । अब जब पिछले दिनों भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों-उपनियमों की अधिसूचना जारी कर दी है तो अमेरिका की भड़ास और बढ़ गई है । उसका कहना है कि वह बाक़ायदा नज़र रखे हुए है कि सरकार इस अधिनियम को किस प्रकार क्रियान्वित करती है । दरअसल भारत सरकार को भी बाक़ायदा नज़र रखनी चाहिंए कि अमेरिका अपने यहाँ के मूल निवासी 'इंडियनस' के अधिकारों को समाप्त करके निरन्तर उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक दो नहीं बना रहा ? और सरकार को अपनी इस नजरसानी का बाक़ायदा घोषणा भी करनी चाहिए ।

संपादकीय

बड़ी टेक कंपनियों की परीक्षा

डिजिटल मार्केट अधिनियम (डीएमए) के प्रवर्तन के कुछ सप्ताह बाद यूरोपीय आयोग ने गूगल, मेटा, एमेजॉन और ऐपल की जांच शुरू की है। यह जांच निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी डिजिटल मार्केट तैयार करने के लिए जरूरी अहम सिद्धांतों का पालन नहीं करने के आरोपों के कारण की जा रही है। ये जांच किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक घटना साबित होगी क्योंकि जिन कंपनियों की जांच की जा रही है वे वैश्विक स्तर पर दबदबा रखने वाली कंपनियां हैं। आयोग खासतौर पर अल्फाबेट के उन नियमों पर गौर कर रहा है जो गूगल प्ले के संचालन तथा गूगल सर्च की खुद को वरीयता देने तथा ऐप स्टोर में ऐपल के संचालन के साथ-साथ सफारी के लिए स्क्रीन के चयन तथा मेटा के 'भुगतान या सहमति मॉडल' पर गौर कर रहा है। इसके अलावा आयोग ने वैकल्पिक ऐप स्टोरों के लिए ऐपल के नए शुल्क ढांचे तथा एमेजॉन की रैंकिंग व्यवस्था को लेकर भी जांच आरंभ की है। डीएमए ने बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को 'गेटकीपर' की अर्हता देने के लिए एक खास लक्ष्य मानक तय किया है। गेटकीपर की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसका बाजार पर अच्छा खासा असर होना चाहिए और उसे यूरोपीय संघ के कई देशों में सक्रिय होना चाहिए। उसे एक मजबूत मध्यवर्ती होना चाहिए, उसे कई तरह के व्यापारों में व्यापक उपयोगकर्ताओं से संबद्ध होना चाहिए और उसे बीते तीन वित्त वर्षों के दौरान इन सभी मानकों पर खरा होना चाहिए। अल्फाबेट, एमेजॉन, ऐपल, बाइटडांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट छह वैश्विक दिग्गज कंपनियां हैं जिन्हें गेटकीपर के रूप में तैयार किया गया है। डीएमए ने गेटकीपरों से मांग की थी कि वे 7 मार्च तक उसके नियमों का पालन सुनिश्चित करें। आयोग का मानना है कि अल्फाबेट और ऐपल के उपाय वित्तीय शुल्कों समेत विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध और सीमाएं लगाने वाले हैं जो डेवलपरों की स्वतंत्र रूप से संचार और पेशकश को बढ़ावा देने तथा सीधे अनुबंध समाप्त करने की क्षमता को बाधित करते हैं। आयोग यह जांच कर रहा है कि गूगल सर्च जो गूगल शॉपिंग, गूगल फ्लाइट, गूगल होटल आदि को प्रमुखता से दिखाता है, क्या वह प्रतिद्वंद्वी सेवाओं पर खुद को प्राथमिकता देता है? वह ऐपल के मामले में इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या वह उपयोगकर्ताओं को आसानी से सॉफ्टवेयर हटाने देता है, आईओएस की डिफॉल्ट सेटिंग बदलने देता है और उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंद की स्क्रीन चुनने देता है जो उन्हें यह इजाजत देता है कि वे अपने आईफोन पर वैकल्पिक ब्राउजर या सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकें। मेटा के मामले में आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं के लिए हाल ही में शुरू किया गया 'भुगतान या सहमति' मॉडल डीएमए का अनुपालन करता है जिसके लिए गेटकीपरों को उपयोगकर्ताओं की सहमति पाने की जरूरत होती है, तब जबकि वे विभिन्न प्लेटफॉर्म सेवाओं पर निजी डेटा को संयुक्त रूप से इस्तेमाल करना चाहते हों या उनका परस्पर इस्तेमाल करना चाहते हों। मेटा का यह द्वैत मॉडल शायद सहमति नहीं देने वालों को सही विकल्प नहीं देता हो। एमेजॉन अपने निजी ब्रांड को तरजीह देता साबित हो सकता है और ऐपल का नया शुल्क ढांचा तथा वैकल्पिक ऐप स्टोरों के लिए अन्य नियम एवं शर्तें डीएमए दायित्वों का विरोधाभासी हो सकता है। आयोग कंपनी के वैश्विक कारोबार के 10 फीसदी तक का जुर्माना लगा सकता है और उल्लंघन दोहराए जाने पर यह 20 फीसदी तक हो सकता है। अतिरंजित हालात में वह गेटकीपरों को कारोबार को बेचने या संबंधित सेवाओं का अधिग्रहण रोकने की इजाजत दे सकता है। डीएमए बड़े डिजिटल एकाधिकार के लिए एक खरी जांच की तरह है। अक्सर इन्हें 'स्वाभाविक' एकाधिकार माना जाता है जहां उपयोगकर्ता एक ही सर्च इंजन, ऑनलाइन स्टोर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रुचि लेता है। एक बार जब प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है तो इसे नेटवर्क प्रभाव का लाभ मिलता है। लेकिन रसूखदार कंपनियों का प्रतिस्पर्धा विरोधी रुख भी प्रतिस्पर्धा को दबाता है। यूरोपीय संघ एक बड़ा और आकर्षक बाजार है और बड़ी से बड़ी कंपनियों को डीएमए के अनुपालन के लिए विवश कर सकता है। जांच के नतीजों के आधार पर डीएमए अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही प्रावधान ला सकता है। इससे सुनिश्चित होने वाली प्रतिस्पर्धा से नवाचार बढ़ेगा जो उपभोक्ताओं और उद्यमियों दोनों के लिए लाभदायक होगा।

मजबूत बैंकिंग जरूरी

तकरीबन एक दशक तक फंसे कर्ज यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में इजाफा होने तथा जोखिम आंकने, खासकर कॉर्पोरेट ऋण के जोखिम के अंकन में शिथिलता के बाद अब देश का बैंकिंग क्षेत्र अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। उसका मुनाफा बढ़ रहा है और निवेशकों का विश्वास नए सिरे से बहाल हो रहा है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री तथा इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के एक सर्वेक्षण में इसकी पुष्टि हुई है। सर्वेक्षण में 23 बैंकों को शामिल किया गया था और उसने दिखाया कि बैंकिंग क्षेत्र कई मानकों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें परिसंपत्ति की गुणवत्ता तथा ऋण वृद्धि शामिल थी। सर्वे के निष्कर्षों में यह भी कहा गया कि बैंक अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) व्यवस्था को अपनाने को भी तैयार हैं और वे जलवायु अनुकूलन तथा उत्सर्जन में कमी की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। इसमें पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां अपनाने को आर्थिक मदद देने, कागज का इस्तेमाल कम करने तथा तटीय इलाकों में जैव ईंधन का इस्तेमाल रोकने जैसे कदम शामिल हैं। ये पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ईएसजी) पहलों का हिस्सा हैं। सर्वेक्षण में शामिल बैंकों में से 83 फीसदी ने कहा कि उनके ऋण मानक आसान हुए हैं या अपरिवर्तित रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक वृद्धि का अनुमान दर्शाया, एनपीए में कमी आने की बात कही और कहा कि क्षेत्रवार जोखिम में कमी आने की उम्मीद है। चुनिंदा क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक ऋण वितरण में इजाफा हुआ है। इसमें अधोसंरचना, लौह और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण तथा औषधि क्षेत्र शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही क्षेत्र हैं जहां एनपीए का स्तर भी अधिक है। अगर इन क्षेत्रों की पहुंच आसान ऋण तक बनी रहती है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंकों को एक बार फिर फंसे हुए कर्ज के चक्र में फंसने से बचना चाहिए। आमतौर पर बैंक अपने बही खातों में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को लेकर संतुष्ट हैं। सर्वेक्षण में शामिल 77 फीसदी बैंकों ने कहा कि बीते छह महीनों में उनके एनपीए में कमी आई है। आधे से अधिक बैंकों का मानना है कि अगले छह महीनों में सकल एनपीए 3-3.5 फीसदी के दायरे में रहेगा। यह आशावाद बेवजह नहीं है क्योंकि सकल एनपीए वित्त वर्ष 2018 के अंत के 11.6 फीसदी से कम होकर गत वर्ष सितंबर में 3.2 फीसदी रह गया था। फंसे हुए कर्ज में नया इजाफा भी कम हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि इससे बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार होगा। यह बहुत राहत की बात है क्योंकि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंक अच्छी हालत में हैं। बहरहाल भविष्य के मुनाफे को लेकर चिंता बरकरार है। सर्वेक्षण में अधिक ब्याज दर वाले जमा की ओर स्पष्ट बदलाव देखने को मिला। करीब 70 फीसदी बैंकों ने कहा कि कुल जमा में करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट (कासा) जमा की हिस्सेदारी कम हुई है। कासा कम लागत वाली जमा राशि है जो बैंकों द्वारा जुटाई जाती है। कम लागत वाली जमा राशि का अर्थ है कम मुनाफा मार्जिन। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के आपस में जुड़े होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने से संकट के समय हालात मुश्किल हो सकते हैं।

दिल्ली में क्या होगा उप राज्यपाल का अगला कदम!

आदिति फडणीस

दिल्ली सरकार को 25 मई के पहले बर्खास्त किया जाएगा या उसके बाद? फिलहाल यही इकलौता प्रश्न है। दिल्ली में उसी दिन लोक सभा चुनाव हैं। उसके पहले कोई कदम उठाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली की सीटें जीतने की संभावना पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच तानों की जंग जितनी लंबी चलेगी, उतने लंबे समय तक केजरीवाल को यह साबित करना होगा कि वह एक दमनकारी सरकार के राजनीतिक बंदी हैं, न कि एक भ्रष्ट व्यक्ति जैसा कि भाजपा दावा कर रही है।

हर दूसरे दिन जेल में बंद मुख्यमंत्री के साथी बाहर यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने जेल से क्या 'निर्देश' दिया है या क्या 'निर्णय' लिया है। इसकी प्रतिक्रिया में उप राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि अनुच्छेद 239 एए और एबी के तहत दिल्ली के उप राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह भारत के राष्ट्रपति को सूचित करें कि ऐसी स्थिति बन गई है जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन संविधान सम्मत तरीके से से नहीं चलाया जा सकता है और वह सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर सकते हैं।

उन्हें इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? लोक सभा में दिल्ली से आम आदमी पार्टी (आप) का कोई सांसद नहीं है। वहां सभी सात सांसद भाजपा के हैं। उप राज्यपाल के प्रतिनिधित्व वाली केंद्र सरकार का वास्तविक लक्ष्य है राज्य सरकार की विश्वसनीयता को प्रभावित करना। आमतौर पर यह काम पार्टी की प्रदेश इकाई का होता है। इस मामले में भाजपा की दिल्ली इकाई इतनी निष्प्रभावी है कि उसे इस काम के लिए संवैधानिक मुखिया की मदद लेनी पड़ी जबकि यह काम निर्वाचित नेताओं का था। विनय कुमार सक्सेना को 2022 में दिल्ली का उप राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले 2015 में उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का अध्यक्ष बनाया गया था। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले सक्सेना ने अपना करियर राजस्थान की एक निजी कंपनी में सहायक अधिकारी के रूप में शुरू किया था। सन 1995 में वह धोलेरा बंदरगाह परियोजना के महा प्रबंधक बनकर गुजरात चले गए जिसे अदाणी पोर्ट्स लिमिटेड और जे के व्हाइट सीमेंट द्वारा विकसित किया जा रहा था। उन्हें न केवल सीईओ बनाया गया बल्कि परियोजना का निदेशक भी बना दिया गया। वर्ष 2000 से आज तक सक्सेना को अगर किसी से डर लगा है तो वह हैं मेधा पाटकर। सन 1990 के दशक में जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरुद्ध बाबा आमटे और मेधा पाटकर के नेतृत्व वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन चरम पर था उस समय सक्सेना ने एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की जिसका नाम था नैशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज (एनसीसीएल)।

उन्होंने आलेख प्रकाशित कराने आरंभ किए और पाटकर की गतिविधियों के विरुद्ध सशुल्क विज्ञापन देने शुरू किए। उन्होंने आरोप लगाया कि वह राष्ट्र विरोधी हैं तथा उन्हें संदिग्ध विदेशी माध्यमों से पैसे मिल रहे थे। पाटकर की मांगें एकदम साधारण थीं- बांध की ऊंचाई बढ़ाने से निश्चित तौर गुजरात और राजस्थान के कई जल संकट वाले इलाकों की प्यास बुझाने में मदद मिलती लेकिन इससे मध्य प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को अपने घरों से उजड़ना पड़ता।

बांध की ऊंचाई बढ़ाने तथा जल भराव वाले इलाके का विस्तार करने से पहले इन लोगों का पुनर्वास करना जरूरी था। इन दलीलों के सही गलत होने से परे नर्मदा बचाओ आंदोलन एक समय गुजरात में बदनाम हो गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने रुख के समर्थन में हरसंभव सहायता जुटाने की कोशिश की। राज्य सरकार की ओर से सक्सेना ने बीड़ा उठाया और पाटकर के खिलाफ मुकदमा लड़ा। बदले में पाटकर ने उनके खिलाफ अवमानना के मामले दायर किए जो अभी भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय काम के लिए सक्सेना का समर्थन यहीं नहीं रुका। उनके स्वयंसेवी संगठन ने ही चिंतक आशिष नंदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद नंदी ने एक लेख लिखा था जिसने राज्य की 'छवि खराब' की थी और 'हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दुर्भावना' बढ़ाई।

आबकारी अधिकारी के संरक्षण में जिले भर में जमकर हो रही शराब की अवैध बिक्री

राजनांदगांव। अविभाजित राजनांदगांव जिले के सभी शराब दुकानों में जमकर भराशाही चालू है। प्रदेश के आबकारी नीति के हिसाब से किसी भी शराब दुकान में प्रति व्यक्ति पांच पौव्वा शराब देने का नियम है और शराब दुकानों में इस नियम का पालन भी बखूबी किया जा रहा है लेकिन यह नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही बनाये गए हैं ऐसा प्रतीत होता है। तीनों जिले के आबकारी अधिकारियों के संरक्षण में अवैध शराम बेचने वाले कोचियों को बिना किसी हिसाब किताब के बोरे में भर भर कर शराब बेचा जा रहा है और प्रति पेटी उनसे उगाही की जा रही है।

होली त्यौहार के अवसर पर आबकारी विभाग ने जिले भर के तमाम कोचियों को जमकर अवैध शराब बेची और मोटी कमाई की। इस मामले को लेकर पायनियर की टीम ने जब जिले के कई शराब दुकानों का मुआयना किया तो पाया कि आम जनता को केवल गिनती की बोतलें दी जा रही हैं। जबकि सुबह शराब दुकान खुलते साथ ही कोचियों को उनके मनमाफिक बोरे में भरकर शराब की सप्लाय की जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोचियों द्वारा आबकारी विभाग को प्रति पेटी के हिसाब से बड़ी रकम का भुगतान किया जाता है।

आबकारी के संरक्षण में कोचिये कर रहे व्यापार

सुबह शराब दूकान खुलने के तुरंत बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में ही कोचियों को बड़ी मात्रा में शराब सप्लाय की जाती है । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किस क्षेत्र में किस कोचिये को कितनी भारी मात्रा में शराब देना है वह सब पहले से तय है और इन सब मसलों के लिए एक फिक्स रकम का भुगतान भी कोचियों द्वारा किया जाता है ।

नकली शराब बनने की भी अपुष्ट ख़बरें

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के आसपास व् कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नकली शराब बनाने का कारोबार भी किया जा रहा है । घुमका सहित कुछ क्षेत्रों में शराब का अवैध व्यवसाय करने वाले कुछ कोचियों के माध्यम से ये नकली शराब खपाई जा रही है ।

रिजल्ट घोषणा के बाद विद्यार्थियों और माता पिता के चेहरे खिल उठे

डीएवी जांता में लगभग 700 अभिभावकों ने बच्चों के रिजल्ट देखने पहुंचे

बेमेतरा। बेमेतरा क्षेत्र के सी बी एस ई एफ्फिलेटेड स्कूल जांता में कक्षा के.जी. वन से कक्षा नवमीं व कक्षा ग्यारहवीं तक का वार्षिक रिजल्ट की घोषणा किया गया। जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुआ सभी छात्रों की चेहरे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसी बीच डी ए वी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के वार्षिक परीक्षा परिणाम सराहनीय रहा, इसी के साथ डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन व सही मार्गदर्शन से व्यक्ति जमीन से आसमान तक कि सफर तय कर सकते हैं, प्रतिभा सुविधाओं का मोहताज नहीं होती, ये साबित किए है, सभी उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम आने के पश्चात सिर्फ छात्र-छात्राओ में ही नही बल्कि पालकों में भी उत्साह का माहौल रहा। सभी प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को मोमेंटो, मैडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। डी ए वी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता में सी बी एस ई शिक्षा व पाठ्यक्रम को लेकर लोगों की सोच बदलने का अद्वितीय कार्य किया जा रहा है। रिजल्ट आने के पश्चात डीएवी में अपने बच्चों के प्रवेश हेतु पालको का उत्साह ओर भी बढ़ा हुआ है। डीएवी स्कूल के प्राचार्य पी एल जायसवाल ने बताया कि आगामी शिक्षा सत्र 24-25 के लिए नए अभिभावकगण, पालको ने भी डी ए वी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता में अपने पाल्य का रजिस्ट्रेशन व एडमिशन कराया हैं। हम विद्यालय से चारों दिशाओं में बस सुविधा भी दिए हैं, जायसवाल ने सभी छात्र-छात्राओं व अभिभावको को बधाई व शुभकामनाएं दी है। परीक्षा परिणाम उत्सव में लगभग 700 माता-पिता व अभिभावकों ने विद्यालय पहुंच कर अपने पाल्य का परीक्षा परिणाम को जाना। रिजल्ट उत्सव में बड़ी संख्या में अभिभावकगण उपस्थित रहे, विद्यालय से शिक्षक ललित देवांगन,अखिलेश पटेल, राहुल पटेल, निशु गुप्ता, अनिल चन्द्रवंशी, ज्ञानेश्वर साहू, पुरुषोत्तम कुमार, अमित कुमार, मनीषा सोनी, दीपिका वर्मा, आयुषी जैन, कैलाश सिंह, गोविंद प्रसाद साहू, राजा तंतुवाय, रेणुका पटेल, छोटु साहू, सुमित्रा पटेल, रितिका साहु, सविता साहु, आरती धीवर, सुखदेव साहू, विजय चंद्राकर, गीता साहू, युवराज, नरेश साहू आदि उपस्थित रहें।

सिविक सेंटर मे हत्या करने के नियत से धारदार हथियार से मारने वाले आरोपियों को भिलाई नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

भिलाई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16.03.2024 को प्रार्थी सुजीत चौधरी पिता रविन्दर चौधरी उम्र 27 साल निवासी श्रीराम जानकी मंदिर के पास राजीव नगर खुर्सीपार भिलाई द्वारा थाना भिलाई नगर उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, 15.03.2024 को सिविक सेंटर भिलाई के पास तीन अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने के नियत से धारदार कटर से प्रार्थी के सीने मे मार दिया था जिसकी रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर मे अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 146/2024 धारा 307, 34 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया 7 प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला जिला दुर्ग द्वारा अज्ञात आरोपीगणो का पता तलाश एवं शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कड़ी दिशा निर्देश दिया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन मे निरीक्षक राजकुमार लहरे थाना प्रभारी भिलाई नगर के नेतृत्व मे टीम गठित कर भिलाई नगर क्षेत्र की सिविल टीम को भी साथ मे लेकर अज्ञात आरोपीगणो का पतासाजी किया जा रहा था एवं प्रतिदिन नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की मानीटरिंग भी की जा रही थी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी. फुटेज एवं आरोपी के हुलिया के आधार पर आरोपी के पतासाजी हेतु मुखबीर तैनात किया गया था। आरोपियों के पतासाजी के दौरान मुखबीर से सुचना मिली कि घटना दिनांक को घटना कारित करने वाले लड़के थाना छावनी के गुंडा बदमाश सोनु उर्फ मोटा सिन्हा, समीर उर्फ गिल्लु एवं उसके साथी होने के संबंध मे जानकारी प्राप्त हुआ जो सुचना की तस्दीक करने पश्चात आरोपीगण सोनु उर्फ मोटा सिन्हा पिता भुषण सिन्हा उम्र 22 साल निवासी इंदु टेक्निकल पुराना बस स्टेंड के पास पावर हाऊस भिलाई। समीर उर्फ गिल्लु जायसवाल पिता प्रेम प्रकाश जायसवाल उम्र 23 साल साकिन पावर हाऊस उत्तम टाकिज के पीछे भिलाई। संजय उर्फ संजु खान पिता स्व. बब्बु खान उम्र 35 साल साकिन पावर हाऊस श्रमिक नगर भिलाई थाना छावनी के घरो मे दबिश देने पर मामले का मुख्य आरोपी सोनु उर्फ मोटा सिन्हा अपने साथी संजु खान के साथ पुलिस का भनक लगते हि अपने स्प्लेंडर मोटर सायकल से राजनांदगांव की ओर फरार हो गये थे जिनको पुलिस के द्वारा पीछा करके पकड़ा गया है। आरोपियों से पुछताछ करने पर अपराध कारित करना स्वीकार किया गया जिनसे घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल एवं धारदार कटर को जब्त कर अग्रिम विवेचना कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

एसआईओ ने जारी किया छात्र घोषणा-पत्र, समावेशी

भिलाई। भारतीय मुस्लिम युवा विद्यार्थियों के संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसआईओ) छत्तीसगढ़ ने छात्र घोषणा-पत्र जारी किया है। साल 2024 के आम चुनावों के मद्देनजर जारी इस घोषणा पत्र का उद्देश्य भारत में शिक्षा, अल्पसंख्यकों और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण करना है। घोषणापत्र में उठाए गए मुद्दों में मांग की गई है कि सभी के लिए अवसर सुनिश्चित करने एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था की जाए। सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और संतुलित विकास के लिए हाशिए पर रह गये क्षेत्रों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाए। रोहित अधिनियम को लागू किया जाए और छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बहाल किया जाए और अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। शिक्षा तक समान पहुंच के लिए अल्पसंख्यक छात्रों की आर्थिक रूप से सहायता की जाए। भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त समाज के लिए भेदभाव विरोधी कानून बनाया जाए। लोगों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा हेतु कठोर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून और गोपनीयता चार्टर बनाया जाए। पर्यावरणीय योजनाओं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ की निधि दी जाए। युवाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे भारत में युवाओं के लिए स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण केंद्र खोले जाएं। सभी के लिए सुलभ शिक्षा की प्रतिबद्धता निभाते हुए प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाए।

देश के युवाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा और अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने हेतु रोज़गार गारंटी अधिनियम लाया जाए। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव मुनव्वर हुसैन और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एस के अमानुल्लाह के साथ प्रदेश सेक्रेटरीज मो. इद्रिस खान व मो. इमरान अजीज उपस्थित थे।

लोकसभा की रणनीति बनाने एनएसयूआई की बैठक आयोजित, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा के साथ नीति निर्धारण कर कार्यकर्ताओ को जिम्मेदारी सौंपी

धमतरी। देशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है, हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दायित्व प्रदान कर रही है। कांकेर लोकसभा चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने भी अपनी रणनीति निर्धारित करने के लिए विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन के निर्देश पर सिहावा विधानसभा अध्यक्ष अंकुश देवांगन के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा के साथ नीति निर्धारण कर कार्यकर्ताओ को जिम्मेदारी सौंपी गई और कांकेर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के पक्ष में मतदान करवाने की अपील की गई। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए काफी अहम है क्योंकि एक ओर अगर पिछले 10 सालों से युवाओं और छात्रों को ठगने वाली मोदी सरकार सत्ता में आई तो युवा वर्ग रोजगार के लिए तरस जाएगा वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के दरवाजे खुलेंगे।

छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के मध्य शैक्षणिक अनुबंध

दुर्ग। विगत 28 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के मध्य एमओयू किया गया। जिसमें सीएसवीटीयू भिलाई के कुलपति डॉ. एम. के. वर्मा एवं आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी.के. पात्रा उपस्थित रहे। इस अनुबंध का उद्देश्य अनुसंधान एवं अकादमिक गतिविधियों के विकास पर दोनों संस्थानों द्वारा सयुंक्त प्रयास करना है। इस एमओयू के तहत फैकल्टी एवं छात्र दोनों संस्थानों में रिसर्च एक्टिविटी हेतु आवागमन कर शैक्षणिक एवं शोध कार्य कर सकते है। इस अनुबंध का उद्देश्य दोनां संस्थान एक दूसरे के साथ मिलकर शैक्षणिक गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट, नये टेक्नोलॉजी आईडिया फॉर इनोवेशन एवं स्टार्ट-अप सेल की स्थापना कर छात्रों को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना एवं एक दूसरे के लिये इनोवेटिव रिसर्च को बढ़ावा देना भी इसका अहम उद्देश्य है, साथ ही अल्पकालिक शैक्षणिक गतिविधि और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। दोनां संस्थान संयुक्त रूप से कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन करा सकते है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रो संजय अग्रवाल, प्रभारी कुलसचिव डॉ. अंकित अरोरा, आयुष विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राजेश हिशीकर, उपकुलसचिव डॉ. एस.के. चटर्जी एवं सहायक कुलसचिव डॉ. मनीष राठोड़ उपस्थित थे।

अफजलुद्दीन हैदर के उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू, जुटेंगे अकीदतमंद

भिलाई। जामा मस्जिद दुर्ग में इमाम रहे हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अफ्ज़लुद्दीन हैदर (र.अ.) का उर्स मुबारक ईदुल फित्र के तीसरे दिन भिलाई कैंप-1 के कब्रिस्तान हैदरगंज में मनाया जाएगा। माहे रमजान के ठीक बाद होने वाले इस उर्स को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हजरत अफ्ज़लुद्दीन हैदर के बेटे और जामा मस्जिद सेक्टर-6 के साबिक इमाम हाफ्जि मौलाना अजमलुद्दीन हैदर ने बताया कि इस मौके पर सुबह फजर की नमाज के बाद से कुरआन ख्वानी का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद सुबह 9 बजे से नात व मनकबत पेश की जाएगी। सैयद हैदर (र.अ.) की दीनी खिदमत पर छत्तीसगढ़ व बाहर से आए उलेमा अपनी तकरीर में रोशनी डालेंगे। तकरीर के बाद सुबह 10 बजे कुल की फातिहा व चादरपोशी होगी और इसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। हाफिज अजमलुद्दीन हैदर ने कहा कि यह उर्स न सिर्फ उनके वालिद का है।

शिष्य ऊंचाई पर पहुंचे यह हमारा गर्व

पचास साल बाद मिले कालीबाड़ी के छात्र और शिक्षक

रायपुर। किसी का चेहरा बदला था, तो किसी के बाल ही गायब हो गए। कोई आईडी कार्ड देखकर दोस्त को पहचान रहा था, तो कोई किसी के चिरपरिचित अंदाज को देखकर ठहाके लगा रहा था। यह नजारा आज तब दिखाई दिया जब कालीबाड़ी स्कूल के 1973-74 बैच के सहपाठी पचास साल बाद फिर मिले। इस पारिवारिक मिलन समारोह में सभी मित्रों के परिवार भी एक-दूसरे से आनंद और उल्लास के साथ आपस में मिल रहे थे। समारोह में उपस्थित गुरूजनों में रॉय सर, आठवें सर तथा बैनर्जी और भागवत सर भी इन अविस्मरणीय पलों के सहभागी बने। गुरूजन इस बात पर प्रसन्न थे कि उनके द्वारा शिक्षीत-दीक्षित छात्रों ने आज ऊंचा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने सबसे व्यक्तिगत पूछताछ कर पारिवारिक हालचाल पूछा। समारोह की शुरुआत सरस्वती पूजा से की गई। स्कूल की प्रार्थना या कुदेंदु तुषार हार धवला का गायन विवेक केलकर, अरुण काठोटे, सुधीर मिश्रा, नरेन्द्र श्रीवास्तव तथा सुनील गनोदवाले ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित गुरूजनों का सम्मान अमरजीत बक्शी, आनंद सुराना, राजेन्द्र खंडेलवाल, सुजीत सन्याल, जगदीश मोटवानी, आशीष दास गुप्ता द्वारा शॉल-श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस अवसर पर कालीबाड़ी के सीनियर छात्र, पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा भी मंचस्थ थे। सभी शिक्षकों ने पचास साल पहले की शिक्षा और अनुशासन को रेखांकित किया तथा छात्रों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद उपस्थित छात्रों ने अपना परिचय दिया तथा नौकरी व पेशे बाबत जानकारी दी। परिचय सत्र के बाद सबने दोपहर भोजन किया। इसके पश्चात मनोरंजक गेम्स तथा गीत-संगीत का सबने लुत्फ उठाया। मिलन समारोह में शहर के बाहर से भी छात्र आए थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश लुनावत ने तथा आभार प्रदर्शन आनंद सुराना ने किया। मिलन समारोह में पचास से अधिक छात्र शामिल हुए।

स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त

दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत जिले में निर्वाचन कार्य को सम्पन्न कराने के लिए स्थैतिक निगरानी दल की नियुक्ति की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए स्थैतिक निगरानी दल के साथ वीडियोग्राफर की ड्यूटी लगाई गई है। जारी आदेशानुसार दुर्ग जिले के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए 51 स्थैतिक निगरानी दल प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62-पाटन के एसएसटी पाईट महादेव घाट नदी के पास थाना क्षेत्र अमलेश्वर के लिए दल प्रभारी उप अभियंता नगर पंचायत पाटन थानेश्वर वर्मा एवं सहायक श्रमायुक्त श्रम निरीक्षक अमित कुमार चिराम को नियुक्त किया गया है। इनके साथ वीडियोग्राफर मनीष की ड्यूटी लगाई गई है। सहायक श्रमायुक्त श्रम निरीक्षक महेन्द्र पाल के साथ वीडियोग्राफर खिलेश की ड्यूटी लगाई गई है। एसएसटी पाईट कुम्हारी टोल प्लाजा के लिए कार्यपालन अभियंता नगर निगम भिलाई जोन-4 के दल प्रभारी अखिलेश चंद्राकर के साथ वीडियोग्राफर मिथलेश कुमार, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण उप अभियंता कार्यपालन अभियंता दल प्रभारी राजेन्द्र कुमार कसेर के साथ वीडियोग्राफर सत्यम कुमार, सेठ रतन चंद्र सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के दल प्रभारी सहायक प्राध्यापक डॉ.उमेश वैद्य के साथ वीडियोग्राफर रूपेन्द्र कुमार। एसएसटी पाईट बेल्हारी पाटन चौक थाना क्षेत्र जामगांव आर के लिए अनुभाग अधिकारी श्रीधर जोशी के साथ वीडियोग्राफर शुभम ठाकुर, स्टेशन अधिकारी सुगंध चौधरी के साथ वीडियोग्राफर मनीष कुमार, अनुभाग अधिकारी रोमन कुमार सिन्हा के वीडियोग्राफर सोहम साहू की ड्यूटी लगाई गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63-दुर्ग ग्रामीण के एसएसटी पाईट कौही (नदी के आगे भखारा जिला धमतरी मार्ग की तरफ) थाना क्षेत्र रानीतराई के लिए कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर के सहायक प्राध्यापक पंकज कुमार जैन को एसएसटी दल का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके वीडियोग्राफर हेमंत रहेंगे। जिला कार्यालय खनिज शाखा खनिज सुपरवाईजर अशोक कुमार गुप्ता के वीडियोग्राफर प्रवीण ठाकुर, वाणिज्यकर अधिकारी दुर्ग वृत्त ओम प्रकाश साहू के वीडियोग्राफर हेमंत की ड्यूटी लगाई गई है।

माहे रमजान में इबादत का दौर जारी, बड़ों के साथ बच्चे भी रख रहे रोजा

भिलाई। रमजान के इस मुबारक महीने में रोज़ा-अफ्तार के साथ इबादत का दौर जारी है। नौजवानों और बड़े-बुजुर्गों के साथ बच्चों में भी रोजा रखने का हौसला बरकरार है। इस्लाम में हर इबादत बालिग होने पर फर्ज हो जाती है जिसको पूरा करना जरूरी होता है। औरतों के लिए भी रमजान माह में दिनचर्या बदल गई है। कुरान की तिलावत करना, शाम के वक्त इफ्तार तैयार करना, आधी रात पूरी होने पर सहरी बनाने की तैयारी करना फिर पांच वक्तों की नमाज़ पढ़ना होता है। जिसमें घर की औरतें मसरूफ रहती हैं। खुर्सीपार जोन 3 की गजाला कुरैशी बताती है कि अल्लाह रोजेदार के लिए जो अर्ज रखा है उसका यकीन फर्ज को पूरा कराता है। 11 महीने खाए पिए है एक माह अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ भूखा प्यासा रहना चाहिए। रूआबांधा निवासी आरिफा इकबाल कहती हैं रोजा हर बालिग मोमिन मर्द ओर औरतों पर फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लाहो अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका खुलासा है कि रोजे का बदला अल्लाह खुद अता फरमाता है। सेक्टर 11 खुर्सीपार निवासी नफीस असलम बताती है जितना सवाब मर्दो को मिलता है उतना ही औरतों को घर पर रहकर इबादत करने, नमाजे तरावीह पढ़ने, तिलावते कुरआन में, अल्लाह के जिक्र अजकार में और दरूद शरीफ पढ़ने में मिलता है। जितना वक्त मिले उसको इबादत में लगाना चाहिए। जोन 2 निवासी शन्नो खालिद जमाल,नूर अस सबा, रिजवाना जुनैद, सोनी मजहर ओर इंजीनियर सबा कुरैशी बताती है दर हकीकत रोजा इस्लाम के अरकान में से एक अहम अरकान फर्ज है। बिला उज्र (वास्तविक कारण) के बिना रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि रोजा नफस (इच्छा, शक्ति) को कंट्रोल करना,भूख व प्यास का अहसास दिलाता है। सबसे बड़ी बात अल्लाह से कुर्ब (करीब) का जरिया है। इंजीनियर कहकशां अंजुम कहती हैं नौजवानों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। बिना वजह घूप में घूमने या गपशप करने बिना मतलब की बातें जिसमें ना दुनिया का फायदा है ओर ना आखिरत का फायदा इससे बचना चाहिए। रोजा रखकर बुराईयों को छोड़ना ताकि आगामी 11 महीने साफपाक दामिनी ओर अल्लाह ओर उसके रसूल सल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने वाली जिंदगी जिएं जिससे लोगों में मोहब्बत अमन इंसाफ ओर सच्चाई आम हो। रोजेदार औरतें बताती हैं कि उनके घरों में बड़ों के साथ बच्चे भी रोजा रख रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं।

छावनी थाना क्षेत्र में आपरेशन ईगल के तहत् एक सप्ताह के अंतर्गत 19 स्थायी वारंटी को कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया

भिलाई। पुलिस महा निरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा कई वर्षो से लंबित स्थायी वारंट का तामीली हेतु आपरेशन ईगल अभियान के तहस सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा सप्ताह भर के भीतर क्षेत्र मे 19 स्थायी वारंट की तामीली कर न्यायालय दुर्ग मे पेश किया जिसमे प्र.आर. जसपाल सिंह, आनंद तिवारी, राम नारायण यदु, विजय शुक्ला, आरक्षक सुनील वर्मा, आकाश तिवारी, त्रिलोक भाटी, संजय सोनी, सुरेन्द्र सिंह, जीत नारायण, चालाक आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

संक्षिप्त समाचार

सीरिया के अजाज प्रांत में कार बम धमाका, हमले में 8 लोगों की मौत; 20 घायल

बेरूत , एजेंसी। रविवार सुबह तुर्की समर्थक बलों के कब्जे वाले उत्तरी सीरियाई शहर के एक बाजार में एक बम विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद एक युद्ध निगरानीकर्ता ने इसकी जानकारी दी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि अलेप्पो प्रांत के अजाज में एक लोकप्रिय बाजार के बीच में एक कार में बम विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में आठ लोग के मारे गए हैं और 23 अन्य घायल हैं। मरने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। ब्रिटेन स्थित ऑब्जर्वेटरी, जिसके पास सीरिया के अंदर स्रोतों का एक नेटवर्क है उसने जानकारी दी कि विस्फोट स्थल पर कई एम्बुलेंस और बचाव कर्मी मौजूद थे। तुर्की सेना और उनके सीरियाई प्रतिनिधियों ने सीमा के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसमें अज़ाज़ जैसे कई प्रमुख शहर और कस्बे शामिल हैं।साल 2011 में सरकार द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने के बाद सीरिया का युद्ध शुरू हुआ और यह एक घातक संघर्ष में बदल गया जिसमें जिहादियों और विदेशी सेनाओं को शामिल किया गया।

एक बार फिर भीषण हमलों से दहला यूक्रेन, रूसी सेना ने रातभर दागे मिसाइल और ड्रोन

कीव , एजेंसी। युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के क्षेत्रों को निशाना बनाया है। समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, रूस ने यूक्रेन पर रात भर 16 मिसाइल दागे हैं। इसके अलावा 11 ड्रोन हमले भी किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर दागे मिसाइल और ड्रोन यूक्रेन की वायु सेना ने एक बयान में कहा कि रूस ने रातभर 16 मिसाइलें और 11 ड्रोन हमले किए हैं। टेलीग्राम पर एक बयान में वायु सेना ने कहा कि यूक्रेन ने नौ ड्रोन और नौ मिसाइलों को मार गिराया है। हालांकि, बाकी मिसाइलों और ड्रोन किस जगह गिरे हैं। उन लक्ष्यों की पहचान नहीं हो पाई है। रूस के हवाई हमलों में हुआ इजाफा जानकारी के अनुसार, बीते एक सप्ताह के दौरान रूस के हवाई हमले की संख्या में जबरदस्त बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। बता दें कि रूस-यूक्रेन के बीच साल 2022 की शुरुआत में जंग छिड़ी थी। साल 2024 शुरू होने के बाद भी दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं थम पाया है।

पाकिस्तान में हुए विस्फोट में 1 व्यक्ति की मौत, 14 अन्य घायल

इस्लामाबाद , एजेंसी। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मारी पेट्रोलियम कंपनी की टीम हरनाई जिले में इलाके में गैस की खोज करने के लिए सर्वेक्षण कर रही थी तभी संवर्धित विस्फोटक उपकरण (आईईडी) में धमाका हुआ। हरनाई के उपायुक्त जावेद डोमकी ने धमाके की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हैं। हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन प्रांत में जारी जातीय संघर्ष की वजह से अक्सर बलूच चरमपंथी सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते रहे हैं। बलूच चरमपंथियों का संघीय सरकार पर प्रांत की खनिज संपदा का दोहन करने का आरोप है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने हमले की निंदा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता प्रदान करें।

ब्रिटेन में खुलेगा दुनिया का पहला 165 मील लंबा ड्रोन सुपर हाई-वे

लंदन एजेंसी। ब्रिटेन में दुनिया का पहला ड्रोन सुपर हाई-वे जून से जुलाई के बीच खुलेगा, जिससे पायलट रहित ड्रोन पूरे देश में हाई-स्पीड डिलीवरी कर सकेंगे। ड्रोन सॉफ्टवेयर कंपनी एल्टीट्यूड एंजेल द्वारा प्रोजेक्ट स्काई-वे के तहत विकसित 165 मील लंबा नेटवर्क मिडलैंड्स में कोवेंटी को दक्षिणपूर्व में मिल्टन कीन्स से जोड़ेगा।

नेतन्याहू पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव, बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन

तेल अवीव, एजेंसी। इजरायल-हमास युद्ध को पांच महीने से अधिक समय हो गया है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली पुलिस ने तेल अवीव में 16 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, हमास की कैद से बंधकों की रिहाई और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों को ट्रैफिक में बाधा डालने और सड़क जाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर 270 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस ने बयान में कहा कि बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने आग लगाकर, पुलिस बैरिकेड को तोड़कर कानून व्यवस्था को बाधित किया। इसके साथ ही सड़कों को बंद करने और पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प भी की। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। सीएनएन ने एक वीडियो का हवाला देते हुए बताया कि पुलिस ने तेल अवीव में अयालोन राजमार्ग पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। साथ ही मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस वाहन में ले जाया गया।

7 अक्टूबर को किया था इजरायल पर हमला

बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला किया था। इस दौरान 1200 से अधिक लोग मारे गए थे और हमास ने लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया था। हालांकि, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ गया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

चुप रहो, मैं तुम्हें लेक्चर दूंगा; भारतीय मूल के राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, हो रही जमकर तारीफ

गुयाना , एजेंसी। गुयाना के भारतीय मूल के राष्ट्रपति इरफान अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पर्यावरण के मुद्दे पर एक पश्चिमी मीडियाहाउस के पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हैं। इसी बीच पत्रकार के सवाल पर वह कहते हैं कि पश्चिम को पर्यावरण के बारे में लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अब आप सुनिए, इस मुद्दे पर मैं लेक्चर दूंगा।

राष्ट्रपति इरफान अली से पत्रकार ने हाल ही में खोजे गए तेल के बड़े भंडार और तेल निकालने को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने कहा कि, आने वाले दोशकों में लगभग 150 अरब डॉलर का तेल निकाले जाने की संभावना है। यह एक बड़ा फिगर है। इसका मतलब हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन भी होने वाला है। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा, क्या आपको हमें लेक्चर देने का अधिकार है। आप कौन होते हैं हमें लेक्चर देने वाले। इस मामले में मैं आपको लेक्चर देता हूं। क्या आप उन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। मैं आपको रोकता हूं। आप जानते हैं को गुयाना के पास इतना वन क्षेत्र है जितना इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का कुल एरिया है। एक ऐसा वन है जो कि 19.5 गीगाटन कार्बन स्टोर करता है और हमने वह वन बचाकर रखा है। इसके बाद रिपोर्टर ने कहा कि क्या इस बात से गुयाना को मनमर्जी कार्बन उत्सर्जित करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपित ने कहा, क्या आपको हमें लेक्चर देने का अधिकार मिल जाता है? हमने जो जंगल बचाए हैं उनका आनंद आप और पूरी दुनिया ले रही है। उन्होंने कहा, गुयाना में दुनिया में सबसे कम जंगल काटे जाते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम के उत्पादन के बाद भी गुयाना नेट जीरो कार्बन वाला देश बना रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे जंगलों के लिए पश्चिमी देशों को भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा, बीती आधी सदी में दुनिया ने आधे से ज्यादा जैव विविधता खत्म करदी। हमने अपने पर्यावरण को बरकरार रखा है। आप कौन होते हैं इसका मूल्यांकन करने वाले। क्या हमने जो पर्यावरण कि रक्षा की है विकसित देश उसकी कीमत चुकाएंगे।

इटली में घटी जन्म दर से एलन मस्क भी हैरान, एक साल में पैदा हुए साढ़े तीन लाख बच्चे

वाशिंगटन , एजेंसी। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार एलन मस्क काफी समय से जनसंख्या वृद्धि में गिरावट का मुद्दा उठाते रहे हैं। मस्क का मानना है कि कम जन्म दर के कारण जनसंख्या का पतन सभ्यता के लिए ग्लोबल वार्मिंग से कहीं अधिक बड़ा खतरा है। अब उन्होंने एक यूरोपीय देश का आंकड़ा शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि वहां की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हम बात कर रहे हैं इटली की। इटली में जन्म दर में पिछले साल फिर से गिरावट आई है। हालांकि इमिग्रेशन (आप्रवासन) के कारण कुल जनसंख्या लगभग स्थिर रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसटीएटी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इटली में 01 जनवरी, 2024 तक लगभग 5.89 करोड़ लोग थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7,000 लोगों की शुद्ध गिरावट है। यह 2014 के बाद से हो रही जनसांख्यिकीय गिरावट को दिखाता है। आंकड़ों से पता चला है कि इटली में पिछले साल 379,000 बच्चे पैदा हुए थे, और जन्म दर 2022 में 6.7 प्रति हजार तुलना में प्रति 1,000 लोगों पर 6.4 बच्चों के बराबर थी। यही आंकड़ा शेयर करते हुए एक्स के बॉस एलन मस्क ने लिखा, 2023 में इटली में केवल 379,000 जन्म हुए, जो 1861 में देश के एकीकरण के बाद से सबसे कम वार्षिक आंकड़ा है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो 2022 की तुलना में 14,000 कम बच्चे पैदा हुए। यानी कुल 4.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं 2008 की तुलना में लगभग 197,000 कम बच्चे पैदा हुए हैं। वर्ष 2008 में पहली बार यहां जन्म दर में गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हुई थी। इसके कारण इटली में महिलाओं से जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या 2022 में 1.24 से घटकर 2023 में 1.2 रह गई। यह स्थिति पूरे इटली में समान रूप से देखी गई है। हालांकि विदेशी लोगों के इटली में बसने से वहां की कुल जनसंख्या लगभग स्थिर रही। इटली में विदेशी मूल के लोग पूरी आबादी का लगभग नौ प्रतिशत है, और इससे जनसांख्यिकीय गिरावट को सीमित करने में मदद मिली। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में हर देश में 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी का विश्लेषण किया गया है। इससे पता चलता है कि जापान (29.8 प्रतिशत) के बाद 23.7 प्रतिशत बुजुर्गों के साथ इटली दूसरे स्थान पर है, लेकिन फिनलैंड (22.9 प्रतिशत), पुर्तगाल (22.6 प्रतिशत), और यूनान (22.5 प्रतिशत) से अधिक है।

पाकिस्तान में रेड कार्पेट बैन, सिर्फ विदेशी महमानों के लिए बिछाया जाएगा

पीएम शाहबाज समेत कैबिनेट मंत्री सैलरी नहीं लेंगे

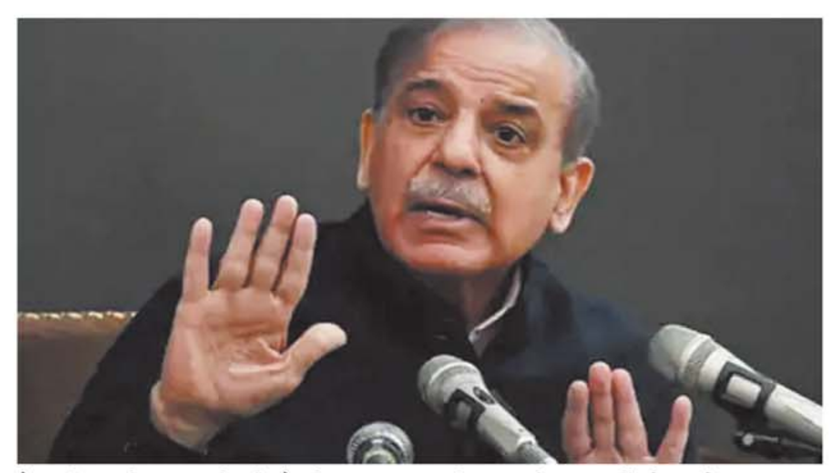

इस्लामाबाद , एजेंसी। पाकिस्तान में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में रेड कार्पेट का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसे सिर्फ विदेशी महमानों के स्वागत में बिछाया जाएगा। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने यह फैसला लिया है।

पीएम शाहबाज शरीफ ने अधिकारियों को आधिकारिक कार्यक्रमों में रेड कार्पेट के इस्तेमाल पर बैन लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में रेड कार्पेट बिछाने की प्रथा पर असंतोष जाहिर किया।

इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री को मिलने वाली सैलरी लेने से भी इन्कार कर दिया है। 18 दिन पहले राष्ट्रपति जरदारी ने भी सैलरी नहीं लेने का फैसला किया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद कैबिनेट के मंत्रियों ने भी सैलरी नहीं लेने की घोषणा की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सैलरी 2 लाख रुपए प्रति महीना होती है। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को सैलरी के तौर पर हर महीने करीब 8 लाख 46 हजार पाकिस्तानी रुपए मिलते थे। यह वेतन 2018 में संसद ने तय किया था। 13 मार्च को जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने ङ्ग अकाउंट पर लिखा- राष्ट्रपति जरदारी देश की मदद करने के लिए अपने कार्यकाल में कोई सैलरी नहीं लेंगे। उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और राष्ट्रीय राजस्व पर बोझ नहीं डालने का फैसला किया है।

डोनाल्ड ट्रंप की विवादित पोस्ट पर बढ़ा हंगामा, राष्ट्रपति बाइडन के समर्थकों ने लगाई फटकार

वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की तस्वीर वाली एक वीडियो शेयर की थी। इस वीडियो में राष्ट्रपति बाइडन के हाथ-पैर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि यह फुटेज एनवाईपीडी के अधिकारी जोनाथन डिलर की मौजूदगी के दौरान लॉन्ग आइलैंड पर कैप्चर किया गया था। वीडियो में ट्रंप के लिए समर्थन व्यक्त करने वाले दो ट्रकों को दिखाया गया है। जिसमें बाइडन की हाथ और पैर बंधी तस्वीर को ट्रक के पीछे दिखाया गया है। हालांकि, ट्रंप द्वारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद जो बाइडन के समर्थकों ने उनकी जमकर आलोचना की। ट्रंप के प्रचार प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने उनका बचाव करते हुए कहा कि यह तस्वीर एक पिकअप ट्रक के पीछे थी, जो राजमार्ग से गुजर रहा था। डेमोक्रेट और लोगों ने न केवल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार के खिलाफ घृणित हिंसा का आह्वान किया। बल्कि वे वास्तव में उनके खिलाफ न्याय प्रणाली को हथियार बना रहे हैं। वहीं, बाइडन के प्रचार प्रवक्ता माइकल टायलर ने सीएनएन को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शेयर की गई यह पोस्ट हास्यपाद है। यह पोस्ट एक रक्तपात की मांग करने की तरह है। ट्रंप नियमित रूप से राजनीतिक हिंसा को भड़का रहे हैं और समय आ गया है कि लोग उन्हें गंभीरता से लें। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह 2024 के चुनाव में हार जाते हैं तो इससे अमेरिकी ऑटो उद्योग और देश के लिए खूनखराबा होगा। उन्होंने अमेरिका के बाहर निर्मित कारों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया।

लेबनान में गोलाबारी से संयुक्त राष्ट्र के चार कर्मी घायल, इजरायल ने हमले से संबंध होने से किया इनकार

बेरूत , एजेंसी। लेबनान के दक्षिण में संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक दल में शामिल तीन पर्यवेक्षकों और एक अनुवादक शनिवार को बम हमले में घायल हो गए। ये लोग जब क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर रहे थे तभी इनके नजदीक टैंक से दागा गया गोला आकर गिरा। इस गोले के टुकड़ों से क्षेत्र में तैनात संयुक्त राष्ट्र के ये कर्मी घायल हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा करते हुए उसे अस्वीकार्य बताया है जबकि इजरायल ने इस हमले से कोई संबंध होने से इनकार किया है। लेबनान का यह इलाका ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के प्रभाव वाला है। यहां पर इजरायल और हिजबुल्ला के बीच बीते आठ अक्टूबर से रह-रहकर लड़ाई चल रही है।

इस बीच, युद्धविराम पर इजरायल और हमास के बीच शनिवार को मिस्त्र की राजधानी काहिरा में फिर से परोक्ष वार्ता शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल काहिरा में मौजूद हैं लेकिन वे मिस्त्र और कतर की मध्यस्थता में वार्ता कर रहे हैं। गाजा की खाद्य समस्या में राहत देने के लिए यूरोपीय देशों का एक और जहाज 400 टन खाद्य सामग्री लेकर साइप्रस से रवाना हो गया है। इसके अगले हफ्ते गाजा पहुंचने की संभावना है।

अमेरिका ने कई अरब डालर मूल्य के बम और लड़ाकू विमान इजरायल को देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस खेप में अमेरिका इजरायल को विभिन्न तरह के 4,800 बम देगा। उल्लेखनीय है कि सामान्य स्थिति में अमेरिका अपने पुराने सहयोगी इजरायल को प्रतिवर्ष 3.8 अरब डालर की सैन्य सहायता देता है। गाजा में इजरायली भीषण सैन्य कार्रवाई के चलते अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रही बाइडन सरकार को घरेलू मोर्चे पर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके इजरायल की सहायता में कमी नहीं की गई है। गाजा में इजरायली हमलों में 75 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई हजार लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी कई हजार लोग बुरी तरह से बीमार है।

हमें निकालकर भारतीयों को दी नौकरी, अमेरिका में टीसीएस पर लगे गंभीर आरोप

न्यूयार्क , एजेंसी। भारत की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) पर अमेरिका में भेदभाव के गंभीर आरोप लगे हैं। टीसीएस के 20 से अधिक कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी नस्ल और उम्र के आधार पर गैरकानूनी तरीके से भेदभाव कर रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। कुल मिलाकर, 22 अमेरिकी प्रोफेशनल ने टीसीएस पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने उन्हें निकालकर एच-1बी वीजा पर आए पर भारतीयों को नौकरी पर रखा।

टीसीएस द्वारा निकाले गए व्यक्तियों में कॉकेशियन, एशियाई-अमेरिकी और हिस्पैनिक अमेरिकी नस्ल के लोग शामिल हैं, जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है। ये लोग अमेरिका के विभिन्न राज्यों से आते हैं। शिकायतों के आधार पर, टीसीएस द्वारा नौकरी से निकाले गए कई व्यक्तियों के पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या अन्य एडवांस डिग्री है। इन लोगों ने आईटी फील्ड की दिग्गज भारतीय कंपनी पर उनके साथ भेदभाव करके कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि कंपनी भारतीयों को फेवर कर रही है। आरोपों के बाद भारतीय आईटी कंपनियों द्वारा एच-1बी वीजा के इस्तेमाल को लेकर जांच शुरू हो गई है। ये वीजा कैटेगरी कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए है।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा दंतेवाड़ा जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न

नितेश मार्क /दंतेवाड़ा /लोकसभा चुनाव नामांकन के पश्चात भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा बस्तर संभाग प्रभारी ने दंतेवाड़ा भाजपा कार्यालय मे अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला कार्यकारिणी की बैठक लेकर कार्यकर्ताओ को बूथ स्तर तक जा कर संपर्क करने हेतु कहा 7 पदाधिकारी व कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चा बस्तर प्रभारी वनवासी मौर्य ने कहा की एक साधारण व गरीब आदिवासी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष महेश कश्यप को भाजपा ने बस्तर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया।भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है इसलिए इसे कार्यकर्ताओ की पार्टी कहा जाता है,इसमें कोई भी कार्यकर्ता छोटा या बड़ा नहीं होता और इसलिए भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है । साथ ही मौर्य ने कहा की भाजपा केंद्र व राज्य सरकार की जितने भी योजनाए है उनका लाभ हर घर एवं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए सभी

कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर संपर्क करना होगा,अधिक से अधिक जरूरतमंद योजना के लाभार्थी बने इसमें सभी को प्रयास करना होगा 7अबकी बार 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिला स्तर,शक्ति केंद्र स्तर में कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सामाजिक संगठनों के साथ भी समन्वय के साथ संपर्क करना होगा । अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारीयो को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष व विधायक चैतराम अटामी ने कहा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी 3 महीना के अंदर ही लगभग सभी गारंटियों को पूरा किया गया हैं और जनता को सीधा लाभ मिलने लगा है। सरकार की लाभार्थी योजनाओं को लेकर घर-घर जाकर वंचित लाभार्थियों को लाभ दिलाने का कार्य भाजपा कार्यकर्ता करे जिससे जनता में विश्वास बना रहे और जरूरतमंद लाभ ले सके ।इस कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं दंतेवाड़ा जिला प्रभारी नन्द किशोर राना, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला महामंत्री पिसे वट्टी, जिला महामंत्री ध्रुवा कुंजाम,भीमा कवासी, अर्जुन,छन्नू ताती,रति भास्कर, डमरू राम वेको, धुरवाराम पोड़ियामी, अनिल ताती व भाजपा के कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

लोकसभा निर्वाचन के दौरान सतत निरीक्षण हेतु संयुक्त दल गठित

अशोक जैन/ कांकेर। / लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान निर्वाचन को प्रभावित करने वाले प्रलोभन को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह द्वारा पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को सतत् निरीक्षण कर कार्यवाही हेतु संयुक्त दल का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक -11 कांकेर (अजजा) के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-79 अंतागढ़ (अजजा) के लिए गठित दल में एसडीओपी पखांजूर श्री रवि कुजूर, आबकारी निरीक्षक श्री ओम प्रकाश, वाणिज्य कर निरीक्षक श्री सत्यम सिन्हा और परिवहन उप निरीक्षक श्री दिपेश खाण्डे शामिल हैं।

इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) के लिए एसडीओपी श्री प्रशांत कुमार पैकरा, आबकारी निरीक्षक श्री गोविंद ध्रुव, वाणिज्य कर निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार ठाकुर और परिवहन विभाग के सहायक ग्रेड-02 श्री त्रिलोकीनाथ बघेल तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-81 कांकेर हेतु एसडीओपी कांकेर श्री मोसीन खान, आबकारी निरीक्षक श्रीमती रानू मरकाम, वाणिज्य कर निरीक्षक श्री संतू राम सलाम और परिवहन विभाग के सहायक ग्रेड-02 श्री प्रकाश चंद्र ध्रुव सतत् निरीक्षण हेतु गठित दल में शामिल हैं।

न्योता भोज : प्राथमिक शाला में बच्चों को भरोसा गया स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन

भारत भास्कर/ बिलासपुरः- छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना में शामिल नेवता भोज के तहत प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना चलाए जा रहे न्योता भोज कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक शाला उसराभांठा विद्यालय नेवसा में शिक्षक एवं रसोइयों द्वारा बच्चों को न्योता भोजन खिलाया गया सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की एवं अतिथियों का स्वागत भाषण भी हुआ। नेवता भोज में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाकर परोसा गया। जिसमें खीर, पुड़ी, चांवल, दाल,आलू मटर,सलाद, पापड़ व लड्डू परोस गए साथ ही उपहार स्वरूप बच्चों को रूमाल वितरण किया गया। कक्षा पहली से लेकर पांचवीं तक के छोटे-छोटे बच्चे नेवता भोज पाकर काफी उत्साहित नजर आये। शासकीय प्राथमिक शाला उसराभांठा के प्रधान पाठक विद्यानंद कश्यप ने स्वयं अपने हाथों से नन्हे मुन्हें बच्चों को भोजन परस कर खिलाया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अभ्यागत के रूप में शैक्षिक समन्वयक रामपुरी ताम्रकार ने कहा की न्योता भोजन से स्वास्थ्य पोषण आहार एवं सामुदायिक सहभागिता सीखने को मिलता है। ग्राम पंचायत सरपंच भरत लाल कश्यप ने कहा कि बच्चे आगे आने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी करें और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। शिक्षक शंकर लाल भारद्वाज ने कहा नन्हे मुन्हें बच्चे गिले मिट्टी के समान है जिसे कुम्हार जिस रूप में चाहे ढाल देता है। उसी प्रकार इन बच्चों को शिक्षक जिस रूप में चाहे गढ सकता है। न्योता भोज कार्यक्रम में मुख्यरूप से स्थानीय संवाददाता - राधेश्याम कोरी, शेखर बैशवाड़े , विजय साहू, पंच में पूर्णिमा देवी साहू, ललित कश्यप, शाला विकास समिति अध्यक्ष सीताराम कश्यप, गण मान्य नागरिक में गोविंद प्रसाद सूर्यवंशी, गौरी शंकर यादव, गोपाल धीवर, परमेश्वर प्रसाद बैशवाड़े के सहित सभी रसोइया एवं शाला के समस्त बच्चे उपस्थित रहे।

हायर इंडिया ने हेक्सा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ एयर कंडीशनर की अपनी सुपर हेवी-ड्यूटी रेंज लॉन्च की

नई दिल्ली। लगातार 15 सालों से नंबर 1 ग्लोबल मेजर एप्लायंस ब्रांड 'हायर अप्लायंसेज इंडिया' ने सुपर हेवी-ड्यूटी एयर कंडीशनर की अपनी नवीनतम रेंज लॉन्च की है। हेक्सा इन्वर्टर और सुपरसोनिक कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ यह नई रेंज 20 गुना तेज कूलिंग और 65ज्ञ बिजली की बचत करने में सक्षम है। हायर इंडिया ने कस्टमर्स -इंस्पायर्ड इनोवेशन्स को तैयार करने और उन्हें बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाने में अपना समर्पण जारी रखा है। नई रेंज मार्केट में एक हाई स्टैंडर्ड सेट करती है क्योंकि हेक्सा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, केवल 10 सेकंड में सुपरसोनिक कूलिंग, फ्रॉस्ट सेल्फक्लीन टेक्नोलॉजी और इंटेली कन्वर्टिबल 7-इन-1 जैसे एडवान्स फीचर्स पर बेस्ड है। समर में क्विक कूलिंग की मांग को पूरा करने और कस्टमर्स की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए, नई रेंज इनोवेशन, डिजाइन और ऊर्जा कुशलता को संगठित रूप से एकीकृत करती है। हायर अप्लायंसेज इंडिया के प्रेजिडेंट एनएस सतीश ने लॉन्च पर कहा, हायर में, हम नई टेक्नोलॉजीज बेस्ड प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने में विश्वास करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स के जीवन को आसान, सुविधाजनक और आरामदायक बनाते हैं।

मतदाता जागरूकता के तहत प्रशासन की अनूठी पहल

जिले के अस्पताल,मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर से जनरेट बिल में मतदाता जागरूकता का सील लगाकर लोगों को मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक

गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता जागरूकता के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता के तहत जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है।इसके तहत जिले के शासकीय जिला अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल स्टोर,रेस्टोरेंट एवं जनरल स्टोर से जनरेट बिल में मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगन युक्त सील लगाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है।इससे मेडिकल पर्ची एवं दुकान से प्राप्त बिल में मतदाता जागरूकता स्लोगन संकल्प एक अभियान शत प्रतिशत हो मतदान एवं 26 अप्रैल मतदान अवश्य करे सूचना युक्त सील लगाए जाने से लोगों को आसानी से मताधिकार की जानकारी मिल रही है।साथ ही मतदाता मतदान दिवस में वोटिंग करने के लिए जागरूक हो रहे है।जिले में संचालित स्वीप गतिविधियों के तहत रबर स्टाम्प सील के माध्यम से जन जन तक शत प्रतिशत मतदान का संदेश निरन्तर दिया जा रहा है।मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान में शासकीय संस्थानों सहित निजी संस्थान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे है। इसके तहत जिला अस्पताल के ओपीडी पर्ची में,निजी स्टेशनरी मार्ट,रेस्टोरेंट,मेडिकल स्टोर जैसे संस्थानों में ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल में मतदाता जागरूकता का सील लगाया जा रहा है। कलेक्टर अग्रवाल के निर्देश पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गार्गी यदु पाल के मार्गदर्शन में जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों की ओपीडी पर्ची में अलग से मुहर लगाकर मतदान के लिए जागरुक करने की नई पहल की जा रही है।स्वास्थ्य केंद्रों के ओपीडी पर्ची में ्रहमन सब परिवार करे हन इरादा,26 अप्रैल 2024 को मतदान करे के वादा की स्लोगन की मुहर लगाकर मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान के लिए जागरुक किया जा रहा है। सील में महासमुंद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान की तारीख 26 अप्रैल 2024 भी अंकित किया गया है।

अवैध महुआ शराब परिवहन करते हुए पुलिस ने तीन लोगों को पड़कर कार्रवाई की है

राजीव वर्मा

एमसीबी--भारत भास्कर--नशे के कारोबार के विरुद्ध संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही एवं अंकुश लगाने के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने महुआ शराब का परिवहन करते पाए जाने पर तीन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है

थाना प्रभारी अमित कुमार कौशिक ने बताया कि मूखबीर के सूचना के आधार पर सड़क दफई हल्दीबाड़ी का रहने वाला राकेश केवट और विवेक कुमार अपने मोटरसाइकिल में महुआ शराब रखकर बिक्री करने हेतु गदबदी बैकुंठपुर की ओर से हल्दीबाड़ी की ओर आ रहा है

सूचना पर रेलवे फाटक गेल्हा पानी के पास घेराबंदी कर मोटरसाइकिल से आते हुए व्यक्ति को रोक नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश केवट तथा विवेक कुमार निवासी सड़क दफई हल्दीबाडी का होना बताया तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति राकेश केवट के हाथ में रखे झोला के अंदर 35 नाग सफेद पारदर्शी पन्नीयों में भरा अवैध महुआ शराब मिला जो आरोपियों को कब्जे

से फुल 22.750 लीटर अवैध महुआ शराब तथा परिवहन कर रहे मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स बिना नंबर का जप्त किया गया है

इसी प्रकार एक अन्य मामले में मुखबिर के द्वारा सूचना मिला कि ग्राम गदबदी गेल्हापानी बैकुंठपुर का रहने वाला संतोष यादव बोरी में महुआ शराब रखकर अपने मोटरसाइकिल ग्लैमर से शराब बिक्री करने हेतु लक्ष्मण झरिया रोड से होते हुए चिरमिरी की ओर आ रहा है

लक्ष्मण झरिया जंगल के पास घेराबंदी कर मोटरसाइकिल से आते हुए व्यक्तियों को रोका गया जिनका नाम पता पूछने पर अपना नाम संतोष यादव निवासी गदबदी बताया तलाशी लेने पर एक सफेद रंग की बोरी के अंदर 20 नग सफेद पन्नीयों में भरा अवैध महुआ शराब मिला जो आरोपी के कब्जे से कुल 13 लीटर तथा परिवहन कर रहे मोटरसाइकिल के लिए नीले रंग का क्रमांक सीसी 15 क 6657 को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना चिरमिरी में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है संपूर्ण कार्रवाई में टी आई अमित कौशिक सहायक उप निरीक्षक शेषनारायण सिंह प्रधान आरक्षक संजय पांडे विश्वनाथ सिंह सुरेश गौड़ आरक्षक अंबुज सिंह बालकरण कुजूर एवं जसप्रीत सिंह का सराहनीय योगदान रहा

सार-समाचार

छत्तीसगढ़ में मोदी की हर गारंटी पूरी होगी : विष्णुदेव साय

अशोक जैन/ कांकेर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ चुनाव प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक विक्रम उसेंडी, सांसद मोहन मडावी, विधायक आसाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम कांकेर लोकसभा संयोजक भरत मटियारा की उपस्थिति में कांकेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने आज शहर में रैली निकाल नामांकन दाखिल किया। भोजराज नाग के नामांकन पश्चात नए बस स्टैंड सभा स्थल में सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व पर आये संकट के लिए चुनाव लड़ रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस को कहीं कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है।

सीएम ने केन्द्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की गारंटी के तहत 18 लाख परिवार को आवास व दो साल के बोनस को सभी किसानों के खाते मे लगभग 12 लाख किसानों के खाते 16 सौ करोड़ रुपये डाला जा चुका है। वहीं किसानों के समर्थन मूल्य में हो रही धान खरीदी की राशि जल्दी ही किसानों के खाता में एकमुश्त दिया जाएगा। किसानों को थोड़ा सब्र करने की जरूरत है क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व के सरकार ने विरासत में हमें खाली खजाना दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा चुनाव के दौरान किए सभी वादे को पूरा करने की बात कही थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की देखा देखी कांग्रेस भी लोक लुभावन वादे जनता से कर रही है परंतु जनता को कांग्रेस के वादों पर कोई भरोसा नहीं है । इन्होंने हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है । कांग्रेस के वादे भी 70 साल से गरीबी हटाओ के नारे की तरह है जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल है । कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा । कांग्रेस में चुनाव से पहले ही भारी भगदड़ मची हुई है। उनके नेता व कार्यकर्ताओ में भाजपा में प्रवेश लेने की होड़ मची हुई है । कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, भाजपा की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि उनके खुद के नेता अपने पूर्व मुख्यमंत्री पर उपेक्षा, भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं । आने वाले कुछ वर्षों में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

विधायक आशा नेताम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की कई फर्जी घोषणाओं को छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 के चुनाव में भी सुना था । घोषणाएं पूरी नहीं हुई कांग्रेस पार्टी की तरह ही कांग्रेस की घोषणाएं भी फर्जी हैं । झूठ का पुलिंदा जनता इसके कई प्रमाण देख चुकी है। सांसद मोहन मंडावी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश का उत्तरोत्तर विकास हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व पटल पर अपनी अलग छवि बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग की चिंता की है और सब का साथ सबका विश्वास सब का विकास के नारे के साथ देश के हर व्यक्ति के विकास के बारे में सोचा है । लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने कहा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा किया था। 5 साल में एक भी महिला को 500 रुपए की राशि नहीं दी गई। जिन लोगों ने 5 साल 500 नहीं दिया अब वह 8000 प्रति महीना देने का वादा कर रहे हैं और यह कहने में उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्म भी नहीं आ रही है यही कारण है कांग्रेस पूरी तरीके से हर जगह से खदेड़ी जा रही है। सभा को विधायक आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया । सभा का संचालन जिला महामंत्री दिलीप जायसवाल ने किया । सभा मे मुख्यमंत्री के समक्ष आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी सहित कई लोगो ने भाजपा प्रवेश किया । इस अवसर पर क्लस्टर प्रभारी अजय चंद्राकर, सह प्रभारी यशवंत जैन, लोकसभा प्रभारी अभिषेक सिंह, सह प्रभारी यज्ञदत्त शर्मा, , भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश लाटिया, पवन साहू, प्रकाश बैस, दीपेश अरोरा, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले, पिंकी शाह, प्रीतम साहू, वीरेंद्र साहू, श्रवण मरकाम, सेवक नेताम भरत निषाद संजय गोलछा सहित बड़ी संख्या में हजारो की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

वेस्टर्न डिजिटल ने सीसीटीवी स्टोरेज के लिए अतिआवश्यक फीचर्स के बारे में बताया

नई दिल्ली। सीसीटीवी एप्लीकेशंस के विकसित होते परिवेश में सिक्योरिटी के लिए पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा अन्य विभिन्न सेक्टर्स जैसे रिटेल मैनेजमेंट और परिवहन में भी स्मार्ट वीडियो का महत्व बढ़ा है। यूज़र-फ्रेंडली विकल्पों से लेकर आधुनिक आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (एआई) युक्त डिवाईसेज़ तक विभिन्न कैमरों की उपलब्धता के साथ भारत में सीसीटीवी बाजार के तेजी से विस्तार करते हुए 3.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2028 तक 8.43 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाने की संभावना है7 स्मार्ट वीडियो सेटअप के महत्वपूर्ण तत्वों में विशेष स्टोरेज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभावी सीसीटीवी ऑपरेशंस के लिए अत्यधिक क्षमता वाले स्टोरेज समाधानों की जरूरत है, ताकि 24/7 वीडियो कैप्चर संभव हो सके। इसके लिए एक विशाल स्टोरेज में निवेश करना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वह ऑन-कैमरा माईक्रो एसडीटीएम कार्ड्स में हो या हार्ड डिस्क ड्राईव में। वेस्टर्न डिजिटल द्वारा डब्लूडी पर्पल प्रो स्मार्ट वीडियो एचडीडी 22 टीबी तक की स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है, जो सीसीटीवी सेटअप के लिए अति उत्तम है।

संक्षिप्त समाचार

युवक पर हथौड़ी से हमला

रायपुर। हाईटेक पार्किंग डुमरतराई के पास एक युवक ने दूसरे युवक से गाली-गलौज कर हथौड़ी से सीर पर मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर माना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अलीम खान 28 वर्ष हाईटेक पार्किंग डुमरतराई का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी अर्पित शर्मा 24 वर्ष ने प्रार्थी से गाली-गलौज कर प्रार्थी के सीर पर हथौड़ी से मारकर चोट पहुंचाया। जिससे प्रार्थी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

बकरा चोर के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर। ग्राम नवागांव खार के पास दो युवकों ने एक महिला का बकरा चोरी कर बेच दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर खरोरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया सुनीता यादव 30 वर्ष कृष्णा चौक खरोरा की रहने वाली है। बताया जाता है कि प्रार्थिया बकरी चराने का कार्य करती थी। बताया जाता है कि आरोपी प्रिंस यादव व पीलू ने प्रार्थिया के 1 नक बकरा को चोरी कर 10 हजार रुपए में बेच दिया और बकरी चरवाहा नरेन्द्र को जान से मारने की धमकी दिया। जिससे प्रार्थिया की शिकायत पर खरोरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 381, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

मोबाइल दुकान से नकदी सहित हजारों रुपए के सामान पार

रायपुर। ग्राम खौना तिगड्डा चौक के पास मोबाइल दुकान के रोशन दान से अंदर प्रवेश कर दो युवकों ने 10 नग मोबाइल और नकदी 10 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी धनेश राय 21 वर्ष देवगांव खरोरा का रहने वाला है। प्रार्थी ग्राम खौना के तिगड्डा चौक के पास मोबाइल दुकान चलाता है। बताया जाता है कि 17 अक्टूबर को आरोपी चंद्रशेखर धृतलहरे व सुनील धृतलहरे नरे प्रार्थी के मोबाइल दुकान में रोशन दान से प्रवेश किया और 10 नग मोबाइल व नकदी 10 हजार रुपए पार कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 457, 380, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

रिसेप्शन पार्टी से जेवर पार

रायपुर। आमोर पार्क तेलीबांधा में आयोजित रिसेप्शन पार्टी से अज्ञात चोर ने 2 नग सोने का अंगुठी, 3 नग चांदी का पायल पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी उत्कर्ष मिश्रा 25 वर्ष कचना खम्हारडीह का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी के यहां आमारे पार्क तेलीबांधा में शादी रिसेप्शन पार्टी चल रहा था। जहां अज्ञात चोर ने स्टेज पर मिले उपहार में से 2 सोने की अंगुठी और 3 चांदी का पायल पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 90 हजार रुपए के असपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

पैदल जा रहे युवक को कार ने रौंदा

रायपुर। रिंग रोड 1 स्थित होटल 38 केस्टट्रल के सामने अज्ञात कार ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।मिली जानकारी के अनुसार मृतक भूतनाथ मंडल 26 वर्ष खुशी रेसीडेंसी तेलीबांधा का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह कल शाम पैदल कहीं जा रहा था, तभी रिंग रोड नंबर 1 होटल 38 केस्ट्रल के सामने अज्ञात कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए भूतनाथ मंडल को कुचल दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म, आरोपी चाचा जेल दाखिल

रायपुर। शराब के नशे में धुत चाचा ने अपनी 16 साल की नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी परिवार में किसी भी सदस्य को देने पर मारने की धमकी भी दी। मामले की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपित चाचा को शराब भट्टी से गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना रामपुर क्षेत्र अंतर्गत निवासरत एक परिवार के सदस्य काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे। घर पर उनकी 16 वर्षीय पुत्री अकेली थी। इसी बीच शराब के नशे में धुत चाचा की नीयत बदल गई और उसने अकेली भतीजी को देख दुष्कर्म किया। जब स्वजन वापस लौटे, तब नाबालिग ने घटना की जानकारी दी। स्वजनों ने बेटी को लेकर सिविल लाइन थाना जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता के स्वजनों ने बताया कि आरोपित शराब का आदी है और हमेशा शराब के नशे में रहता है। मना करने पर नहीं मानता था और अब नशेड़ी ने दुष्कर्म किया है।

डायरिया के जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई?

शहर में टैंकर नहीं आया तो बोर का गंदा पानी पीने मजबूर हुए नागरिक..

- 80 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित, महापौर बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई

रायपुर/ संवाददाता

राजधानी के संकल्प सोसाइटी में बोर का गंदा पानी पानी से हर घर कोई न कोई डायरिया की चपेट में आ गए हैं. बता दें कि पिछले साल भी इसी बोर का पानी पाने से 66 लोग डायरिया से पीड़ित हुए थे. वहीं दो लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद टैंकर से वहां पानी सप्लाई हो रहा था पर 15-20 दिन से टैंकर नहीं आने से लोग बोर का पानी पी रहे थे जिसके चलते डायरिया की चपेट में आ गए. अब सवाल उठने लगे हैं कि अब तक ज़िम्मेदार लापरवाह लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? आखिरकार किसके कहने पर पानी का सप्लाई रोका गया ? संकल्प सोसाइटी स्थित बोरवेल को पिछले बार भी सील किया गया था. यह मामला नगर निगम की जानकारी में भी था. क्या पीड़ित परिवारों को निगम मुआवज़ा देगा ? इलाज में जो भी खर्चा हुआ है क्या उसकी भरपाई निगम करेगा ? इस मामले में महापौर एजाज ढेबर ने कहा, मामले में कार्रवाई हुई है या नहीं, जानकारी ले लेता हूं. अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. नगर पालिका निगम रायपुर के कमिश्नर अबिनाश मिश्रा का कहना है कि 88 मरीज डायरिया से पीड़ित नहीं थे. जिनका हल्का फुल्का है उसको भी डायरिया कहोगे क्या, फिर लल्लूराम डॉट कॉम की टीम ने कमिश्नर को बताया कि यह हमारा डेटा नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग का है. फिर कमिशनर ने कहा, नोटिस जारी किया जा चुका है. वहीं संकल्प सोसाइटी के लोगों ने कहा, पिछले साल भी 66 लोगों को डायरिया हुआ था. दो लोगों की मौत हुई थी तब से नगर निगम हमारी सोसाइटी में टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन बीच में 15-20 दिनों तक पानी सप्लाई नहीं की. ऐसी स्थिति में मजबूरन फिर से बोरवेल का पानी पीना पड़ा. इसके चलते सभी डायरिया की चपेट में आ गए. पानी सप्लाई बंद होने की शिकायत कार्यालय में की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और हम सभी डायरिया की चपेट में आ गए. वहीं सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा कि घर पीछे डायरिया से पीड़ित हैं. उस घर में नीचे से ऊपर तक पानी ले जाने में बहुत दिक्क़त होती है. अब निगम बाहर टैंकर लाकर खड़ा कर देता है.

पीने का पानी भी बदबूदार डायरिया का खतरा

नया रायपुर के सेक्टर 30 अटल आवास कैंपस में गंदगी, अवैध पार्किंग, पानी समेत अन्य समस्याओं से रहवासी परेशान हैं. इन समस्याओं को दूर करने जनप्रतिनिधि भी कोई सुध नहीं ले रहे. आज सरपंच ने ग्रामीणों के साथ एनआरडीए के सीईओ को ज्ञापन सौंपा और जल्द समस्याओं को दूर करने की मांग की. ज्ञापन में बताया गया कि सीवर लाइन जाम होने से कॉलोनी के सभी गार्डन और मकान के नीचे में गंदी बदबूदार पानी भर गया है.

साईं संजयदेव मसन्द साहिब व उनकी धर्मपत्नी माता अनुपमा देवी मसन्द के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन

रायपुर/ संवाददाता

मसन्द सेवाश्रम के तत्वावधान में स्थानीय सिंधु पैलेस में अहमदाबाद की निज वैकुंठधाम दरबार के गादीनशीन साईं संजयदेव मसन्द साहिब व उनकी धर्मपत्नी विख्यात प्रवचनकार माता अनुपमादेवी मसन्द जी के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सेवाश्रम द्वारा इस अवसर पर पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश दरयाणी एवं महासचिव बलराम पी. आहूजा का भी अभिनन्दन किया गया। पूज्य शदाणी दरबार के संत साईं उदयलाल, पूज्य गोधरीधाम की महंत माता मीरादेवी कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मसन्द सेवाश्रम के पीठाधीश साईं जलकुमार मसन्द साहिब ने की। मंच पर उनके साथ कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदराणी व संयोजक भारतीय सिंधु सभा की युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन तारवाणी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रायपुर की पूज्य सिंधी पंचायतों, पुरुष व महिला समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारियों ने मंचस्थ संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, सभा को अपनी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले सेवा कार्यों से अवगत कराया तथा मंचस्थ अतिथियों के साथ ग्रूप फोटो खिंचवाए। मुख्य अतिथि साईं संजयदेव मसन्द साहिब ने इस अवसर पर सभा को अपने परिवार द्वारा गुरु दर की सेवा के 400 साल के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज गुरु नानक देव साहेब जी की सेवा से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा में समर्पित रहें। उन्होंने बताया कि सन् 1702 में गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से मसन्द कुलगुरु गादी की शुरुआत हुई । बटवारे से पहले सिंध में गुरुबानी की सीख को जन-जन तक पहुँचाने का दायित्व इसी मसन्द कुलगुरु परिवार पर था। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दी हुई अनमोल बख्शीशें आज भी इस परिवार के पास मौजूद हैं।

छग की शराब नीति से भाजपा का असली चेहरा आया सामने:विनोद

- पिछले 5 साल हल्ला मचाने वाले भाजपाई नई शराब नीति पर मौन
- भाजपा ने शराब से 11 हजार करोड़ कमाई करने का लक्ष्य रखा

रायपुर/ संवाददाता

पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर हल्ला मचाने वाले भाजपाई आज मौन साधे बैठे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही भाजपा के तमाम छोटे-बड़े नेता खामोश हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए शराब से 11 हजार करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। अहाता के लिए जो दरें तय की गई थीं, उनसे पांच गुना अधिक राशि पर टेंडर निकाला गया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में सभी भाजपाई प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे थे। अब जब प्रदेश में उनकी (भाजपा) सरकार है। तब उन्हें किस बात का इंतजार है। केंद्र व प्रदेश में डबल इंजन के सरकार वालों को तत्काल प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करनी चाहिए। लेकिन, शराब में कमाई का लक्ष्य बढ़ाकर तथा दुकानों में शराब की वेरायटी बढ़ाकर प्रदेश में पहले से और अधिक शराब बिक्री का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। प्रदेश की जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जुमलेबाज सरकार प्रदेश के आधी आबादी को शराब परोसने की तैयारी कर रहा है।

धरा फाउंडेशन द्वारा रायपुर के डगनिया सब्जी बाजार में पॉलिथीन की रोकथाम के लिए थैला वितरण किया

कौशिक ने कांग्रेस पर कसा तंज

कांग्रेस को कोरबा सीट से हार की चिंता सताने लगी

रायपुर/ संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी के विधायक और लोकसभा चुनाव के लिए कोरबा सीट के संयोजक धरमलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस को कोरबा सीट से हार की चिंता सताने लगी है, इसीलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सरोज पांडेय की उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे हैं। विधायक धरमलाल कौशिक ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का नाम लिए बिना उन पर तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता से पूछ लीजिए सभी कह रहे हैं कि सरोज पांडेय जीत रही है और भाजपा का सांसद बनेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीट की बात करने वाले सरोज पांडेय के आने के बाद खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद जब आप मतदाता के पास वोट लेने जाते हैं तो उन्हें 5 साल का हिसाब भी देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल के बाद मतदाताओं को हिसाब देते हैं। मतदाता भी पूछते हैं कि 5 साल में आपने क्या किया? संसद को भी बताना पड़ता है कि 5 साल में उसने क्षेत्र के लिए क्या किया। क्षेत्र में आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि हम आपको वोट दें? जनता सवाल करेगी और जनप्रतिनिधि को जवाब देना पड़ेगा।

शराब घोटालाः पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे को हाईकोर्ट से राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शराब घोटाला मामले में उनके खिलाफआर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर पर हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने अंतरिम राहत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस दौरान शासन की तरफ से जवाब पेश करने एसीबी ईओडब्ल्यू ने जवाब पेश करने समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शराब घोटाले की जांच एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा जारी रहेगी। सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय कथित शराब घोटाला मामला सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। ईडी के एक्शन के बाद कई बड़े नेताओं और राज्य सरकार के नौकरशाहों के नाम सामने आए थे। ईडी ने अपनी जांच में यह पाया कि राज्य सरकार की सरकारी दुकानों से ही नकली होलोग्राम वाली शराब बेची गई।

केंसर से बचाव एवं मतदान जागरूकता वांकाथान........

रायपुर/ संवाददाता

शहर के मरीन ड्राइव तेलीबांधा तालाब परिसर में रविवार प्रात: 06 बजे से सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन केंसर से बचाव एवं मतदान जागरूकता के लिए वांकाथान का आयोजन बालको मेडिकल सेंटर, लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) स्टे फिट विथ मी ग्रुप, माई.एफएम., रिलायंस लाईफ सांईस मेफेयर, शिंराज, अजय पब्लिसिटी, मरविक, योगा इंस्टीटयूट सहित विभिन्न सामाजिक संगठनो के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रूप से आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्वास्थ्य संवर्द्धन के लिए एरोबिक्स, जुंबा, सड़क सुरक्षा तथा मतदाता जागरूकता हेतु संगीतमय नुक्कड़ नाटक सहित अन्य रोचक कार्यक्रमों के साथ केंसर से बचाव के उपायों तथा उपचार के प्रबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा,अध्यक्ष संजय शर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि मात्र सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाने मात्र से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संभावना लगभग 40 प्रतिशत तक कम हो जाती है गत वर्ष सड़क दुर्घटनाओंमें मृत्यु कारित 4017 लोगो ने हेलमेट एवं 673 ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। इस अवसर पर स्टे फिट विथ मी ग्रुप प्रमुख शुभांगीजी एवं टीम ने उर्जावान जुम्बा तथा स्वास्थ्य वर्द्धन के लिये ऐरोबिक्स के साथ-साथ नशे में वाहन चालन।

शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही

सी-विजिल के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का हुआ निराकरण

रायपुर/ संवाददाता

लोकसभा निर्वाचन - 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के सी-विजिल एप (सिटिजन विजिल एप) पर लोगों से प्राप्त हो रही शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति में सी-विजिल के माध्यम से प्राप्त सभी 197 शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि आम नागरिकों से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें सी- विजिल के माध्यम से मिल रही हैं। सी-विजिल पर मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रीना बाबासाहेब कंगाले स्वयं प्रतिदिन मिलने वाली शिकायतों पर हुई कार्रवाई की निगरानी कर रही हैं। लोकसभा निर्वाचन - 2024 के दौरान राज्य में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित सी- विजिल एप्लीकेशन को और भी सशक्त बनाया गया है। अब आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफएवं वीडियो के साथ-साथ ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकेंगे। यदि कोई नागरिक राज्य में आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सी-विजिल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटनास्थल की एक फोटो या 2 मिनट की वीडियो या ऑडियो क्लिपिंग बनाकर एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या एप्प में पंजीकृत होकर भी की जा सकती

है।पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में शिकायत करने पर उपयोगकर्ता को शिकायत निराकरण के पश्चात उसकी सूचना भी दी जाएगी। यह एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए एंड्राइड/आईओएस दोनो पर उपलब्ध है। सामान्य मामलों में शिकायतों पर कार्यवाही 100 मिनिट के भीतर पूरी कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी। सीविजिल एप का उपयोग करते हुए नागरिक निर्वाचन अवधी के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाए बिना ही आनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीविजिल एक आसान ऐप है जो प्रयोक्ता अनुकूल तथा उपयोग करने में आसान है। यह एप्लिकेशन सतर्क नागरिक को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी तथा फिल्ड सत्यापन इकाई (उड़न दस्ते / स्थैतिक निगरानी दलों) से जोड़ती है जिसके द्वारा एक तेज तथा सटीक रिपोर्टिंग, कार्रवाई एवं अनुवीक्षण तंत्र तैयार होता है। नागरिकों द्वारा शिकायत करने की प्रक्रिया गूगल प्ले स्टोर /एप्पल स्टोर से सीविजील एप डाउनलोड करें। नागरिक या तो मोबाइल नम्बर और ओटीपी के माध्यम से लाग-इन कर सकते हैं या गुमनाम रूप से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का फोटो/वीडियो/आडियो कैप्चर करें। पूर्व से रिकार्ड किए गए फोटो/ वीडियो/ आडियो अपलोड नही किए जा सकते।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक,संपादक-संदीप तिवारी द्वारा अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग-मोवा रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित एवं छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग -मोवा रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित।
(पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) फोन:-9301031000, 0771-6556444 bharatbhaskar222@gmail.com